20 फरवरी, 2025 ✯ वर्ष 34, पृष्ठ संख्या 60, अंक 02

राजस्थान सुजस

राजस्थान बजट

हर घर खुशहाली 2025-26

द्वितीय अद्वितीय बजट

अभिव्यक्ति

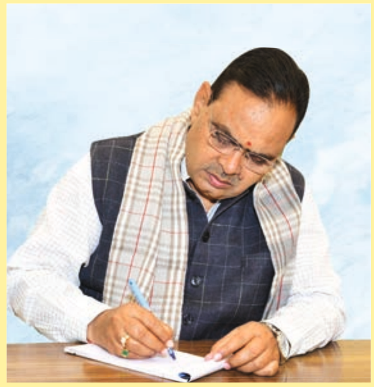

नवीनता का दोबारा सृजन ही वसंत है

ऋतुएं हमारे जीवन में गति और नवाचार का पर्याय हैं। यह सृजनात्मक सोच की राह खोलती हैं। वसंत पंचमी ऋतुराज के आगमन का उत्सव है। इस ऋतु में पेड़-पौधों में नव कोपलें उगती हैं। वसंत आते ही पृथ्वी झूम उठती है। चारों ओर खुशहाली का वातावरण छा जाता है। नवीनता का दोबारा सृजन होना ही वसंत है।

भगवद् गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'मैं ऋतुओं में वसंत हूं'। इसका आगमन जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। प्रकृति की छटा में उतरता पीला रंग हर किसी के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह सृजन बढ़ाने वाला और तनाव कम करने वाला है। विज्ञान भी मानता है कि पीला रंग प्राण शक्ति है। मनौवैज्ञानिक मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन को दूर करने में काफी हद तक कारगर है। इस ऋतु का प्रभाव मानव जीवन में आशावाद और सकारात्मक सोच लाता है। वसंत में बदलाव आगे बढ़ने और विफलताओं का सामना कर नवीन रास्ते सृजन करने की प्रेरणा देते हैं। वसंत ऋतु इसलिए भी सुहाती है क्योंकि इस समय दूर तक सरसों के पीले रंग के पुष्पों की चादर छा जाती है। बचपन में जब मैं दूर-दूर तक सरसों के ऐसे खेत देखता था तो मन भरता ही नहीं था। आज भी जहां भी सरसों के फूल खिलते हैं, तो मैं उन्हें देखने के लिए रुक जाता हूं। वहां खेतों में खड़ा ही रह जाता हूं। ये पीले फूल देखकर हर किसान के मन में उत्साह और उमंग भर जाते हैं।

वसंत पंचमी ज्ञान, विद्या एवं कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी पर्व है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के ही दिन भगवान ब्रह्मा जी की जिह्वा से वाणी, ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। वसंत पंचमी का महत्व शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गहरा है। संसाधनों के अभाव में शिक्षा में बाधा नहीं हो, इसलिए हमारी सरकार राजकीय विद्यालयों के बच्चों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने और संस्कारित पीढ़ी तैयार करने में जुटी हुई है।

हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाया जाए। एक लक्ष्य यही है कि शिक्षा के जरिए चहुंमुखी विकास हो। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। सही ज्ञान और उत्तम शिक्षा से ही समाज का कल्याण संभव है। हमें ज्ञान को परमार्थ के लिए लगाना चाहिए। इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ऋतुएं हमें चरैवेति-चरैवेति की प्रेरणा देने के साथ ही नवीन सोच के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इनमें वसंत सृजन और सौन्दर्य के साथ समावेशन को इंगित करती है। अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई शुरूआत करने का साहस रखें और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो आइए इस अमृतकाल में हम सब मिलकर वासंती प्रेरणा को आत्मसात् कर 'आपणो अग्रणी राजस्थान' और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करें।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

प्रधान संपादक
सुनील शर्मा

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
रवि वर्मा

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 9587916395
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड
लागत मूल्य 33.30 रुपये

वर्ष : 34, अंक 02 | फरवरी, 2025

इस अंक में

अभिव्यक्ति -नवीनता का सृजन...	02
शब्द भावना	04
बजट पूर्व संवाद	05
संपादकीय	06
बजट 2025-26	07
झीलों के शहर में तितलियां...	30
एग्रीस्टेक - किसानों की डिजिटल पहचान	34
'मानस' की पहल, मानस का भला	38
त्वरित न्याय: सुशासन का पर्याय	40
जिला पंच गौरव योजना - अलवर	42
जल आत्मनिर्भरता - सुरक्षित भविष्य	44
मरू महोत्सव	46
माही महोत्सव में अंचल के रंग	47
सांभर महोत्सव में 2 लाख पावणें	48
युवाओं की उम्मीद हो रही पूरी	50
भगवान देवनारायण की 1113 वीं जयंती	52
किसान, श्रमिक... उत्थान	53
सामयिकी	54
परीक्षा पे चर्चा	58
धरोहर - श्री जगदीश धाम मन्दिर, कैमरी	59

कृषि बजट 18

अन्नदाता की उन्नति समृद्धि की गारंटी 27

ग्रीन बजट 22

6000 से अधिक वरिष्ठ जन को हवाई यात्रा 36

प्रयागराज के महाकुंभ में राजस्थान सरकार 29

श्रद्धासुमन 57

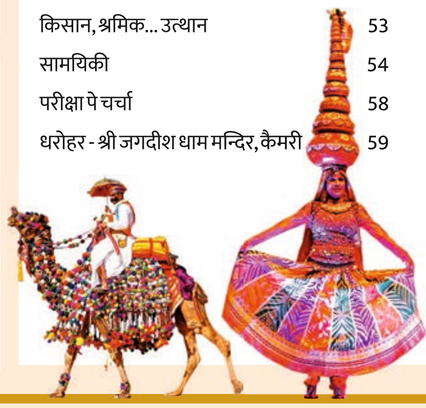

शब्द भावना

"प्रधानमंत्री विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब हमारी संस्कृति और संत, ऋषि व मुनियों की विरासत का प्रतीक है। विश्व का हर व्यक्ति महाकुंभ में जाने के लिए लालायित नजर आया। महाकुंभ की सुनियोजित व्यवस्थाओं के लिए केन्द्र सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार का आभार!"

- मुख्यमंत्री

- प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए, विकसित एवं उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सदन की मर्यादा कैसे रहे, यह सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्यों की जिम्मेदारी है।
- जल संचय हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। जल आत्मनिर्भरता प्रदेश की समृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए अहम है।
- राज्य सरकार आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, बारिश के पानी का अधिक से अधिक उपयोग हमारी प्रमुख प्राथमिकता है।
- किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
- सशक्त पंचायतीराज और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है, गांवों के विकास की बागडोर सरपंचों के हाथों में है, किसानों-पशुपालकों की उन्नति से ही ग्रामोदय का सपना साकार होगा।
- मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है जिनसे हमारी विरासत मजबूत होती है। हमारी सरकार प्रदेश में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।
- यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अनुसार देश में चार ही जातियां- किसान, मजदूर, युवा एवं महिला हैं। इन चारों जातियों के उत्थान से ही देश और प्रदेश का उत्थान होगा।
- हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है।
- राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशानुरूप हमारी सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ विरासत संरक्षण के कार्य कर रही है।
- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
- प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के तहत हुए एमओयू को हर हाल में धरातल पर लागू करने के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित रखा जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- राज्य सरकार उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते

बजट पूर्व संवाद

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025-26 के बजट में जनाकांक्षाओं को जानने के लिए जनवरी-फरवरी माह में चिकित्सा, उद्योग, किसान, मजदूर, खेल जगत के प्रतिनिधियों के साथ ही आर्थिक, कला एवं अन्य विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट में उनकी अपेक्षाएं जानीं। इन बजटपूर्व संवादों में राज्य कर्मचारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उद्योग-व्यापार, युवा एवं खेल, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, एनजीओ एवं सिविल सोसायटी और किसानों सहित विभिन्न समूहों के उपयोगी विचार और सुझाव लिये गए जिन्हें बजट में शामिल किया गया।

बजट 2025-26 की प्रति के लिए QR कोड स्कैन करें।

संपादकीय

भविष्य का मानचित्र, संगम की दिव्यता

बजट किसी भी सरकार का मात्र एक अंकगणितीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि उस पथ की रूपरेखा होती है, जिस पर सरकार आने वाले दिनों में लोककल्याण के लक्ष्य साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाती है। यह लघु स्केल पर वह मानचित्र होता है जो निकट और सुदूर भविष्य में राज्य और राष्ट्र विकास की यात्रा को नए आयाम देता है और हर व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में समृद्धि, खुशहाली और "आज से अच्छे कल" का भरोसा जगा देता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट, "विकसित भारत" की संकल्पना को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। स्वयं प्रधानमंत्रीजी के शब्दों में यह बजट युवा, किसान, श्रमिक, महिला और सभी वर्गों की "उम्मीदों का बजट" है, जो उनके संघर्षों को समझता है और उन्हें नया रास्ता दिखाता है।

इसी प्रेरणादायक मार्ग पर अग्रसर होकर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया। राजस्थान सरकार का यह द्वितीय बजट "अद्वितीय" होने के साथ-साथ "नवोन्मेषी दृष्टिकोण" से परिपूर्ण है, जो राज्य के समग्र विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को इंगित करता है। इस बजट में पहली बार प्रदेश का "ग्रीन बजट" भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण की संरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ग्रीन बजट के समावेशी रूप में शामिल योजनाओं में जनकल्याण, ग्रामीण विकास, उद्यमशीलता, ऊर्जा और प्रकृति जैसे "विकास के साथ प्रकृति संरक्षण" के सभी घटक शामिल हैं।

जब प्रदेश और देश की आर्थिक-सामाजिक उन्नति का भविष्य गढ़ा जा रहा है, ऐसे में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा के अनुपम प्रतीक के रूप में एक नया अध्याय रच दिया है। यहां की अद्वितीय पवित्रता और आभा ने न केवल लाखों श्रद्धालुओं के हृदय को छुआ, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संगम की पवित्र धाराओं में स्नान कर व्यक्तिगत आस्था के साथ सनातन संस्कृति की दिव्यता का संदेश भी दिया। यह क्षण एक सजीव श्रद्धा का प्रतीक बनकर भारतीय संस्कृति और आस्था की महत्ता को विश्वभर में उजागर करने में सफल रहा। मुख्यमंत्री जी ने संगम स्थल पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कर एक और इतिहास रच दिया, जहां उन्होंने देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए।

रंगों और उल्लास के पवित्र पर्व होली की स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के साथ, बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करते हुए, फरवरी माह का यह विशेष अंक आपके सामने प्रस्तुत है।

प्रधान सम्पादक

बजट 2025-26

19 फरवरी, 2025

"राजस्थान के जन-जन, प्रदेश के कण-कण को समर्पित बजट"

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संसद में फरवरी माह के प्रथम दिन प्रस्तुत किए गए बजट में भारत के 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में भारत का वर्ष 2025-26 का केन्द्रीय बजट एक ऐसा बल गुणक है, जो बचत, निवेश, खपत और विकास की दिशा में देश को अग्रसर करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर से मुक्त रखने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले नजर आते हैं।

विकसित भारत का जो रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसी राह पर राजस्थान को अग्रसर कर विकसित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का वर्ष 2025-26 का विकासोन्मुखी बजट उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा 19 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत हैं बजट 2025-26 के प्रमुख बिन्दु...

राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ....

- **राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जो विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम होगा।**
- **राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।**

- वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां।
- वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये का राजस्व व्यय।
- वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये।
- वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपये जो GSDP का 4.25 प्रतिशत है।
- GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान।

राजकोषीय संकेतक

राजस्व प्राप्तियां
2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये

राजस्व व्यय
3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये

राजस्व घाटा
31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये

राजकोषीय घाटा
84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपये

GSDP
19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये

पेयजल

- 20 लाख घरों में कनेक्शन
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारंभ 5,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य
- एक हजार ट्यूबवेल और एक हजार 500 हैंडपम्प
- JJM O&M हेतु नीति, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1,050 पद सृजित

"आगामी वर्ष में 20 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार कार्य करेगी। नगरीय क्षेत्रों में घर-घर नल से जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। इसमें 5 हजार 830 करोड़ रूपए की लागत से काम किया जाएगा।"

ऊर्जा

प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक साल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी काम करेगी। इसके अलावा, 50 हजार कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

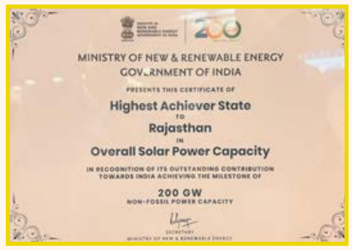

- आगामी वर्ष 6 हजार 400 मेगावाट (MW) से अधिक अतिरिक्त उत्पादन
- 5 हजार 700 मेगावाट (MW) ऊर्जा उत्पादन के कार्य
- रबी, 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20 हजार 700 मेगावाट बिजली सप्लाई
- 50 हजार नए कृषि कनेक्शंस तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शंस
- अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था समाप्त
- निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगा वाट (GW) ऊर्जा का उत्पादन
- 765 केवी का एक; 400 केवी के पाँच; 220 केवी के तेरह; 132 केवी के अट्ठाइस एवं 33/11 केवी के 133 GSS की स्थापना
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से नि:शुल्क सोलर प्लांट्स, 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह नि:शुल्क
- अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स स्थापित

सड़क

❝ राजस्थान में स्टेट हाइवे, बाइपास, रेलवे ओवर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज आदि के निर्माण, विकास और सुधार के लिए 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। राज्य में 2,750 किमी से अधिक लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, जिनकी लागत लगभग 60 हजार करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्यो के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरूस्थलीय इलाकों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये होगी। प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड़ के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। ❞

- State Highways, Bypass Roads, Flyovers, Elevated Roads, ROBs व RUBs, Bridges आदि के निर्माण, repair तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य
- 9 Green Field Expressways 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई, 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से Hybrid Annuity Model (HAM)/BoT पर
- लगभग 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-चतुर्थ चरण, एक हजार 600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना
- अटल प्रगति पथ, 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में Cement Concrete, लागत 500 करोड़ रुपये
- 15 शहरों में 'Ring Roads' के निर्माण कार्य हेतु DPR, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, लागत 575 करोड़ रुपये
- जयपुर शहर के Traffic की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ रुपये के कार्य
- जयपुर में Bus Rapid Transit System (BRTS) को हटाया जाना
- Roadways के लिए GCC Model पर 500 नयी बसें, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) Jaipur Metro का कार्य हाथ में, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत
- जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में Metro के विस्तार हेतु DPR
- समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु Comprehensive Mobility Plan
- 'पंचगौरव योजना' को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य
- डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपये
- सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए **'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम'**, 150 करोड़ रुपये का fund
- SCSP एवं TSP Funds की राशि में वृद्धि, एक हजार 750 करोड़ रुपये
- गुरु गोलवलकर Aspirational Blocks Development Scheme, 35 Aspirational Blocks के लिए
- महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGS) योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
- स्वामित्व योजना, Drone Survey कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे

नगरीय विकास

- Civic Amenities - Parking, Renovation, Residential Flats, Bus Stands आदि के विस्तार एवं उन्नयन, 780 करोड़ रुपये के कार्य
- जयपुर एवं उदयपुर में आवासीय फ्लेट्स की योजना
- द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन
- प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार Street Lights
- 7 वर्षों की अवधि की **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना**, लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये की लागत
- समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में Solid Waste Management सम्बन्धी कार्य
- ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु GCC model पर 4 हजार हूपर
- 500 Pink Toilets का निर्माण, 175 करोड़ रुपये की लागत
- 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment का कार्य
- 296 शहरों में Waste Water Management तथा इससे Treated Water का उद्योगों, कृषि आदि में पुन: उपयोग
- 30 नगर परिषदों में Mechanised Transfer Stations की स्थापना
- संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में Sewerage Gap कवर करना
- 2 हजार किलोमीटर पुरानी Sewerage Lines का आगामी 4 वर्षों में rehabilitation का कार्य
- 100 अत्याधुनिक Robotic three-in-one सीवरेज सफाई मशीनें
- 14 उच्च शहरीकृत शहरों एवं इनके 42 Satellite Towns में पर्यटन, Heritage, Command Control Centre व बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य

औद्योगिक विकास

"हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। हमने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एमएसएमई, एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है तथा अब तक 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है।"

- Investment facilitation हेतु 'Single Window - One Stop Shop', Online Permissions की संख्या को बढ़ाकर 149 करना
- विभागों हेतु Competitive Index
- Rising Rajasthan MoUs के क्रियान्वयन को गति देने के लिए PMU का गठन।
- Flatted Factory की व्यवस्था लागू, Plug and Play Model पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित।
- Service Sector में निवेश हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy
- कोटा में Toy Park, निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ व बूंदी में Stone Parks, सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में Ceramic Park, DMIC के अन्तर्गत Pharma Park की स्थापना, भीलवाड़ा में Textile Park का विस्तार तथा **सांगानेर-जयपुर में Block Printing Zone** की स्थापना।
- Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy
- 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना के लिए 150 करोड़ रुपये।
- Private Industrial Parks/Estates में CETP हेतु सहायता
- DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks
- 'PM Gati Shakti' updation System बनाना।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

"प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हेरिटेज पर्यटन, नाइट टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान भी किये गये हैं। प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों के पुनरूद्धार के कार्य करवाए जाएंगे।"

- प्रथम बार IIFA Awards का आयोजन गुलाबी नगरी-जयपुर में
- पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए वर्ष 975 करोड़ रुपये
- Heritage Tourism को बढ़ावा , Iconic Tourist Destinations के रूप 10 Sites का विकास
- प्रदेश में Night Tourism को बढ़ावा देने हेतु (100 करोड़ रुपये)
- ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं Heritage Walk
- लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र
- जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये
- संस्कृति पोर्टल- गांवों, मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना
- संभाग स्तर पर Hospitality Skill Centres
- पुष्कर-अजमेर, रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेश जी-सवाई माधोपुर, जीण माता-सीकर, तनोट माता मंदिर व रामदेवरा-जैसलमेर, दाऊ मदनमोहन-भरतपुर व देशनोक-बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधायें (95 करोड़ रुपये)
- प्रदेश के विभिन्न झीलों के लिए सौन्दर्यीकरण का कार्य
- त्रिवेणी संगम - बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को विकसित करना
- 600 मंदिरों पर दीपावली, होली एवं रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रमों का आयोजन
- आदिवासी बाहुल्य जिलों 100 करोड़ रुपये व्यय कर 'Tribal Tourist Circuit' विकसित
- Rural Tourism को बढ़ावा, 10 गांवों को विकसित करना
- War Museum-जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधायें
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा ,50 हजार AC Train से तीर्थ यात्रा
- विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये ,मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह
- जयपुर, वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष गोविन्द देव जी कला महोत्सव के आयोजन
- कोटा Airport के निकट Aero City, माउंट आबू-सिरोही में Aero Sports Activities शुरू
- 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाना
- प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूं में Flying Training Organisation (FTO)
- जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में Hop-on Hop-off बस सेवा

युवा विकास एवं कल्याण

- 'राजस्थान रोजगार नीति-2025', 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष
- एक लाख 25 हजार (एक लाख पच्चीस हजार) पदों पर भर्तियाँ
- निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत Interest Subsidy, 5 लाख रुपये तक Margin Money
- एक हजार 500 नये Startups बनाते हुए 750 से अधिक Startups को Funding
- हैदराबाद, बैंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में i-Start Facilitation Desks
- प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counselling की स्थापना
- 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर
- कोटा में Vishwakarma Skill Institute
- 8 नवीन ITIs, 36 ITIs का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण
- 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
- 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय
- जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना
- मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना
- 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में upgradation
- विद्यालयों में Class-rooms, Labs, Computer Lab एवं toilets का निर्माण, 225 करोड़ रुपये का व्यय
- 15 हजार विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना
- एक हजार 500 विद्यालयों में Atal Tinkering Labs
- 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gyms एवं खेल मैदान

"बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन के प्रावधानों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। युवाओं के विकास एवं कल्याण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपये खर्च कर विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। चार लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में आगामी वर्ष में सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी। निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।"

- अलवर, अजमेर व बीकानेर में Digital Planetariums तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के Science Centres में Innovation Hubs की स्थापना
- कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex
- SMS Stadium, जयपुर में Badminton Academy तथा उदयपुर में Lacrosse Academy, जयपुर में Shooting Range मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में Boxing Rings की स्थापना
- जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में Synthetic Tracks का निर्माण
- खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन
- एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर Part Time प्रशिक्षक की भूमिका
- द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी Sports Quota
- नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र
- कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

"स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में जन-जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का 'मा' कोष गठित किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के विशेष केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेज इस योजना में जोड़े जाएंगे। ट्रक, बस ड्राइवरों तथा दर्जी, बढ़ई, नाई आदि कारीगरों की आंखों की जांच कर नि:शुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए 'मा' नेत्र वाउचर योजना लागू की जाएगी।"

- **आमजन की नि:शुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये से 'MAA कोष' का गठन।**
- **MAA योजना में Interstate Portability लागू, Geriatric Care Packages, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के Packages, Oral Cancer हेतु Package, विशेष योग्यजनों हेतु Packages**

- समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics
- प्रदेश को TB मुक्त बनाना, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU-NAAT (ट्रू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता
- HIV संक्रमित सहित अन्य high risk prone महिलाओं की Cervical Cancer की screening
- Haemodialysis सुविधा हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 Beds,
- गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centres भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
- डीग में जिला चिकित्सालय, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, 10 नये ट्रोमा सेंटर
- 148 Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM) की स्थापना
- 'Tertiary Care System' को सुदृढ़ करने के लिए एक हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
- पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर के Vitreo Retina Surgery Unit का उन्नयन
- मेडिकल कॉलेज-बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड क्षमता के Spinal Injury Centres की क्षमता वृद्धि
- मेडिकल कॉलेज-कोटा में Cancer Unit एवं Cottage Ward हेतु 195 करोड़ रुपये
- समस्त संभाग मुख्यालयों पर Ultra Advanced Burn Care Centres
- RIMS जयपुर के अधीन Geriatric Healthcare Resource and Training Centre
- सभी संभाग मुख्यालयों पर Dedicated Geriatric Centres (रामाश्रय) का उन्नयन
- दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु संभागीय स्तर के Rehabilitation Centres का उन्नयन
- संभाग स्तरीय अस्पतालों में Fibro Scan Machines की स्थापना
- Critical Care, ICU, SNCU, Labour Room, Operation Theatre आदि हेतु Specialized Nursing Cadre
- Oxygen Plants का operation and maintenance
- Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS)-जयपुर का उन्नयन, 500 करोड़ रुपये व्यय
- 750 चिकित्सकों तथा एक हजार 500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित
- 'Fit Rajasthan' अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान, diet में edible oil की मात्रा में न्यूनतम 10 प्रतिशत कमी करने के लिए भी प्रेरित
- नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
- हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालायें

- **70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही नि:शुल्क दवा**
- **आँखों की जाँच कर नि:शुल्क चश्में उपलब्ध करवाने के लिए MAA नेत्र वाउचर योजना (MAA- NVY) लागू**

सड़क सुरक्षा

- Delhi-Jaipur, Jaipur-Agra तथा Jaipur-Kota Highways पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 'Zero Accident Zones'
- दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 Black Spots के सुधार
- 20 Trauma Centres का सुदृढ़ीकरण PPP Mode पर करने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 25 Advanced Life Support Ambulances

सामाजिक सुरक्षा

- अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं/एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह
- स्वयंसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाना, 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम
- एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs/Equipment उपलब्ध, 150 करोड़ रुपये का व्यय
- Artificial Limbs/Equipment की गुणवत्ता के सम्बन्ध में Research हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना'
- माटी कला से जुड़े कलाकारों को 2 हजार Electric Wheels (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें
- अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में One Time Settlement Scheme (OTSS)
- 'Gig and Unorganised Workers Development Fund'- Unorganised Sector के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा Coverage, 350 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास
- समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 (तीन हजार दो सौ पचास) रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह
- सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 Bedded सरस्वती Half Way Homes
- 10 जिला मुख्यालयों पर Girl Child Care Institutes
- प्रत्येक Block पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र
- बालिकाओं को 35 हजार Scooty वितरण
- महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख
- राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का Non Banking Financial Company/Corporation के रूप में उन्नयन, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को, 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण, 3 लाख लखपति दीदियां लाभान्वित
- गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू, लगभग 2 लाख 35 हजार महिलायें लाभान्वित
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध, 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार
- खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ना
- 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर 'अन्नपूर्णा भण्डार'

"राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को अगले वर्ष से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रति माह कर दिया है।"

कानून व्यवस्था

"हमने आते ही कानून का राज स्थापित किया तथा संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। परिणामस्वरूप महिला अत्याचार के मामलों में 10.61 प्रतिशत की कमी आई है।"

- Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम'
- 2 वर्षों में पुलिस विभाग को एक हजार वाहन उपलब्ध, 3 हजार 500 नवीन पुलिस पद सृजित
- पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए replacement basis पर 500 वाहन
- Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना, 350 करोड़ रुपये व्यय
- विचाराधीन बंदियों की पेशी Video Conference (VC) के माध्यम से करवाये जाने के लिए 400 VC Nodes की स्थापना
- कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS प्रणाली
- सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
- कारागार प्रशिक्षण संस्थान-अजमेर का Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research के रूप में क्रमोन्नयन
- उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय-शाहपुरा-जयपुर, रींगस-सीकर
- पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय-रायपुर-ब्यावर, खाटूश्याम जी-सीकर
- 8 नवीन साईबर पुलिस थाने
- ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर में जिला एवं सैशन न्यायालय
- ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

अटल ज्ञान केन्द्र

सुशासन

- आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में **"अटल ज्ञान केन्द्र"**
- Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना
- राज्य के अधिनियमों को de-criminalise करने तथा redundant प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम
- विभिन्न विभागों के कार्यों को online कर paperless करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Tablets, 250 करोड़ रुपये का व्यय
- विभिन्न विभागों हेतु 450 (चार सौ पचास) नवीन वाहन
- 400 करोड़ रुपये से नवीनतम तकनीक आधारित RajNET 2.0
- RajNET 2.0 के माध्यम से Connectivity की क्षमता में दोगुनी वृद्धि
- चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Broadband Connectivity

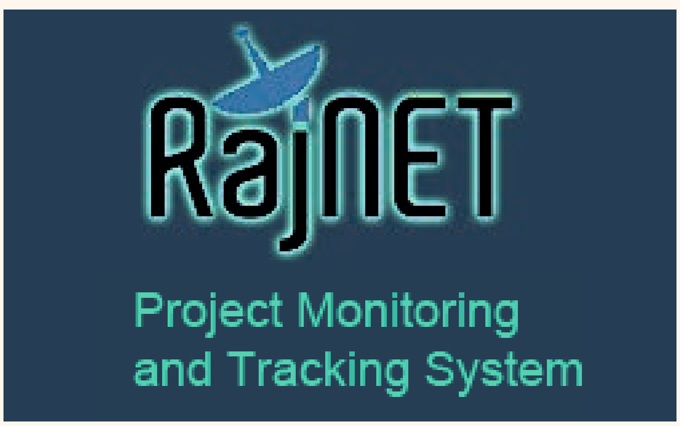

- Disaster Recovery Data Centre, जोधपुर
- Brahmagupta Centre of Frontier Technologies 300 करोड़ रुपये के प्रावधान
- भवन विहीन 20 उप तहसीलों, 10 तहसीलों तथा 7 उपखण्ड कार्यालयों के भवनों का निर्माण
- पुराने जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन एवं जिला परिषद् भवनों का पुनर्निर्माण, कोटा में मिनी सचिवालय
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केन्द्र
- नवस्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

कार्मिक कल्याण

- मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि
- समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
- NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि
- न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
- सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रेल, 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ देय
- पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
- पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक
- पत्रकार साथियों को क्षेत्र में Exposure Tour की सुविधा

कृषि बजट

हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में दी जा रही 8 हजार रुपये की राशि को बढ़ा कर 9 हजार रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है। किसानों को गेहूं के एमएसपी पर दिए जा रहे 125 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के स्थान पर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। पिछले बजट में हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी, अब इस बजट में इस योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। गोशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान बढ़ा कर 50 रुपये प्रति दिन किया जाएगा।

- राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रुप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
- मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
- धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये
- Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये
- Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित, 342 करोड़ रुपये का व्यय
- संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये
- 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-500 करोड़ रुपये का व्यय
- बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टोंक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय
- Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान,एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय
- 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
- PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि भी बढ़ाकर 150 रुपये
- राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य
- आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centres
- आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान, एक लाख कृषक लाभान्वित
- 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये)
- मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट
- Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना

- बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize की स्थापना
- भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना
- लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़ रुपये का व्यय
- 2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Polyhouse/Shednet, Plastic Mulching, Low Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान
- मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce
- एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण
- Farmer Producer Organizations (FPOs) के 100 सदस्य कृषकों को Israel सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना
- Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन
- ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय
- Gopal Credit Card योजना के अन्तर्गत संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान
- दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
- आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित GSS स्थापना के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन (Relaxation)
- नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों (KVSS) की स्थापना
- अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क
- कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडियों में Power Cleaning Machines
- बारां में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र
- 3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण
- 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा /क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी

- 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय
- पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या बढ़ाकर 200 किये
- Milk Products उपलब्ध करवाने तथा Milk Plants की processing capacity बढ़ाने एवं पशुआहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपये के कार्य
- नवीन दुग्ध संयंत्र-अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर; 225 करोड़ रुपये की लागत
- नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र-राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर; 150 करोड़ रुपये की लागत
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13 हजार लाख (तेरह हजार लाख) लीटर, एक हजार नवीन सहकारी समितियों/संग्रह केन्द्रों की स्थापना
- गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन
- 200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र
- 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
- 50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
- 50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
- बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab
- 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती

कर-प्रस्ताव संबंधी बिन्दु

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किये गये संरचनात्मक एवं नीतिगत सुधारों से प्रदेश में इस वर्ष में 26,393 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि संभावित है, साथ ही सभी वर्गों को सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है।

आगामी वर्ष आमजन और व्यवसायियों को निम्नलिखित राहतें प्रदान की जा रही हैं-

- VAT Amnesty के तहत वर्ष 2017 में Repealed Commodities के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये तक की Demand को माफ किया जाना तथा इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर शत-प्रतिशत छूट।
- निरस्त खनन लीज के साथ ही प्रभावी खनन लीज मामलों के लिये भी एमनेस्टी स्कीम।
- ई-रवन्ना संबंधी Overloading के प्रकरणों में Compounding राशि में 95 प्रतिशत तक कमी।
- Stamp Act तथा Excise Act के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में Demand राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराये जाने पर ब्याज एवं Penalty में शत-प्रतिशत छूट तथा वर्ष 2020 से 2022 तक के प्रकरणों में Penalty में शत-प्रतिशत तथा ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट।
- Motor Vehicle Taxation Act के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक तक का बकाया कर 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराने पर नष्ट होने के बाद के समस्त कर, देय पेनल्टी और ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट।
- दिनांक 1 फरवरी, 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित Warehouses को Regularize किया जाना।
- नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड एवं भवनों की 31 मार्च, 2024 तक की बकाया लीज राशि 30, सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

1. निवेश

- प्रदेश को वर्ष 2030 तक $ 350 Billion economy बनाने का लक्ष्य रखते हुये प्रदेश को निवेश हेतु और अधिक Competitive बनाने की दृष्टि से Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)- 2024 के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किये जा रहे हैं-
- MSME इकाईयों की नई वृहद परिभाषा तथा Expansion पर लाभ।
- RIPS-2022 के साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ।
- RIPS-2024 के साथ RIPS-2022 में भी लाभ हेतु Turnover की परिभाषा में Extended Arm (Subsidiaries इत्यादि) के साथ किया गया व्यवहार अनुमत।
- किसी कम्पनी के Director अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कम्पनी में भी Director होने से ऐसी अन्य कम्पनी उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ के लिये पात्र माना जाना प्रस्तावित।
- Agro Processing Scheme-2019 के समय के लम्बित प्रस्तावों को निस्तारण की स्वीकृति।
- **खनन पट्टाधारकों के लिए -**
  - क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस 5000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये।
  - राजकीय भूमि में एकत्रित Overburden के साथ ही गैर सरकारी भूमि पर स्थित Overburden Dumps के M-Sand सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50 प्रतिशत की छूट।
- आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लॉटों की नीलामी Pre-embedded Clearance के साथ।

2. आम आदमी को राहत

- पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी।
- भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों के मामलों में भी दिया जाना प्रस्तावित।
- पति-पत्नी के संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हेतु सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करते हुये योजना का सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित।

3. Ease of Doing Business

- Taxation सम्बन्धी प्रकरणों में Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई के साथ ही जिला स्तर पर Facilitation Desks के माध्यम से Document submission एवं Verification की सुविधा।
- GST एवं VAT के अन्तर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण की गारंटी।
- नवीन Rajasthan Value Added Tax Bill, 2025 लाया जाकर इसके अन्तर्गत-
    - First Point Taxation की प्रक्रिया के साथ ही Act के प्रावधानों का उल्लघंन De-criminalise.
    - 40 लाख रुपये टर्नओवर तक पंजीयन की छूट के साथ ही पंजीयन हेतु Security के प्रावधान समाप्त।
    - जीएसटी की तर्ज पर Self Assessment व्यवस्था लागू।
    - नवीन एक्ट के प्रावधानों के तहत अपील करने पर स्वत: ही स्थगन।
- MV Act के अन्तर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां।
- राज्य से बाहर ले जाये जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एकबारीय कर के रिफण्ड हेतु आवेदन की निर्धारित समयावधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष।
- अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाये गये वाहनों के One Time Tax की गणना Portal के माध्यम से करने और पंजीकरण की व्यवस्था पूर्णतया ऑनलाईन किया जाना प्रस्तावित।
- बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में Approved Lay Out Plan के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी Evaluation की सुविधा।
- Fire NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा Fire NOC की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित।
- वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में प्रतिबन्ध को पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रस्तावित। साथ ही The Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 को संशोधित कर नया अधिनियम भी लाया जाना प्रस्तावित।

4. Green Growth

- औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से Green Growth Credit Policy लायी जाकर नये निवेशकों के साथ-साथ पहले से स्थापित उद्योगों को Ecomark आधारित Green Technology /Goods के उपयोग/उत्पादन पर विभिन्न छूट एवं रियायतें।

5. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- 50 अतिरिक्त उप-पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन।
- 60 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में Centre of Excellence for Mines and Minerals की स्थापना।
- उदयपुर में Institute of Mines एवं जोधपुर स्थित MBM University में Petro Campus की स्थापना।
- उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाईपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, 2025 लाई जाने के साथ ही आगामी वर्ष में 1.25 लाख घरों को Piped Gas Supply ।
- वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग के अनुरूप खनन विभाग में भी Faceless Management की व्यवस्था तथा विभाग का पुनर्गठन प्रस्तावित ।
- खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कम्पनी के रूप में 'Rajasthan Mineral Exploration Limited' का गठन प्रस्तावित।

6. Additional Resource Mobilization (A.R.M.)

- पचपदरा-बालोतरा स्थित 'HPCL Rajasthan Refinery Limited' द्वारा माह अगस्त, 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारम्भ होने के फलस्वरूप बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोज़गार के अवसरों के सृजन के साथ ही आगामी वर्ष Petroleum उत्पादों पर VAT के रूप में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन (A.R.M.) भी प्राप्त होना संभावित।
- साथ ही, Land Pooling, Land Aggregation, InvITs के माध्यम से Asset Monetization किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे 4 हजार 750 करोड़ रुपये का A.R.M. सम्भावित।

प्रदेश का प्रथम
ग्रीन बजट

सदन में इस वर्ष प्रदेश का
प्रथम ग्रीन बजट (हरित बजट) प्रस्तुत किया गया।

"सम्पूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है। ग्रीन ग्रोथ के महत्व एवं आवश्यकता का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है- "For us, protection of environment is an article of faith. We have natural resources because our previous generations protected these resources. We must do the same for our future generations. We have to move towards 'Zero Defect and Zero Effect'. Zero defect in production with no adverse effect on the environment.""

छाया - पदम सैनी

"प्रदेश के प्रथम ग्रीन बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिन्दुओं पर विशेष फोकस देने का विनिश्चय किया गया है, जो इस प्रकार हैं-"

1. Climate Change Adaptation
2. Forest and Environment – Biodiversity/ Ecology
3. Sustainable Agriculture, Water Harvesting /Recharge
4. Sustainable land use
5. Green Energy
6. Recycling and Waste Disposal – Circular Economy
7. Clean Tech Development
8. Green Audit
9. Capacity Building–Education, Skilling
10. Green Funding

बजट :- भावी कार्य

- प्रदेश के अधिसूचित 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों-रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी व धौलपुर-करौली में स्थित चौकी, नाका एवं Anti-Poaching Camp में 35 करोड़ रुपये की लागत से मूलभूत सुविधाओं का विकास
- बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त वन्यजीव अभयारण्यों, Conservation Reserves तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रों में Prey-base में वृद्धि हेतु 30 करोड़ रुपये की लागत से 20 Prey-base Augmentation Enclosures स्थापित किये जायेंगे।
- घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल Rearing Centre स्थापित किया जायेगा।
- सवाई माधोपुर-करौली क्षेत्र में स्थानीय समुदायों तथा विशेषज्ञों की सहायता से विलुप्त होती सियागोश (Caracal) प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।
- Man-Animal Conflict से वन्यजीवों को समय पर rescue करने तथा उपयुक्त स्थान पर translocate करने हेतु 5 rescue वाहन मय उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।

वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अंतर्गत 27 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो कि कुल स्कीम एक्सपेंडीचर का 11.34 प्रतिशत है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किये गये विभिन्न विभागों के कार्यों में ग्रीन ग्रोथ से सम्बन्धित बिन्दुओं का समावेश किया गया है, जैसे-Renewable Energy, Sustainable Agriculture Circular Economy-Waste Management & Recycling, E-Vehicles इत्यादि! इनके साथ ही विशेष Green Initiatives (Key Green Initiatives-KGIs) भी निर्धारित किये गये हैं, ये हैं-

1. Climate Change Adaptation :

- यद्यपि Inter Govermental Panel on Climate Change (IPCC) ने पर्यावरण में वर्ष 2050 तक समुचित सुधार की अपेक्षा की है तथापि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये गये "मिशन लाइफ" से प्रेरणा लेते हुए, इस बदलते क्लाइमेटिक सिनेरियो के अनुरूप परिवेश तथा जीवनशैली को ढालना होगा। प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, डेजर्ट इकोसिस्टम एवं लैण्ड मैनेजमेंट ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में कार्यप्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग की पद्धति में परिवर्तन की दृष्टि से 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान-2030 बनाया जाएगा।
- इसके साथ ही, 150 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाएगा।

2. Forest and Environment – Biodiversity/ Ecology :

- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आगामी वर्ष, मिशन हरियाळो राजस्थान के अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
- समस्त कृषकों एवं अन्य Stakeholders को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर बढ़ाये जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फोरेस्ट (टीओएफआर) पॉलिसी तथा एग्रो-फोरेस्ट्री पॉलिसी लायी जाएगी।
- वन एवं वन्य जीव संरक्षण की कार्ययोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्य कराये जायेंगे।

3. Sustainable Agriculture, Water Harvesting /Recharge :

- रासायनिक उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए-
- नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अन्तर्गत कृषकों को दिये जा रहे सम्बल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक लाख कृषकों तथा बायो-एजेंट्स एवं बायो-पेस्टीसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
- प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिये जाएंगे। साथ ही, ऐसे किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी।
- जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डियों में दुकान, भूखण्ड का आवंटन करने की नीति लायी जायेगी।
- वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के अन्तर्गत आगामी वर्ष 4 हजार 700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के एक लाख 10 हजार कार्य करवाये जाएंगे। इन पर 2 हजार 700 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

4. Sustainable land use :

- विकसित राजस्थान/2047 हेतु जीआईएस आधारित ग्रीन लैण्ड यूज प्लान बनाये जाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा- चरागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास एवं ध्वनि प्रदूषण के निवारण हेतु जोन्स की पहचान एवं प्लानिंग कर आवश्यक सुधार हेतु आगामी वर्ष 45 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

5. Green Energy :

- राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सतत् वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही सौर उपकरणों के निरन्तर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए

सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाएगा। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के के साथ ही, अब पीएचईडी के पम्पिंग स्टेशन्स को भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (हैम) पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इन्डक्शन कुक टॉप-कुकिंग सिस्टम वितरित किये जाएंगे।

6. Recycling and Waste Disposal – Circular Economy :

- सर्कुलर इकॉनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकॉनॉमी इन्सेन्टिव स्कीम-2025 लायी जाएगी। इस Scheme के माध्यम से-
- रिसाइकिल/रीयूज के क्षेत्र में शोध के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जायेगा।
- सर्कुलर इकॉनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमईज तथा स्टार्टअप्स को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

बजट :- भावी कार्य

- मुकुन्दरा राष्ट्रीय अभयारण्य में वन्यजीवों के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)-भरतपुर में संरक्षण गतिविधियों-Internal Road, पाल मरम्मत आदि विभिन्न कार्य 20 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
- अभेड़ा Biological Park, कोटा में Master Plan के अनुसार 35 प्रजातियों हेतु शेष रहे 22 Enclosures बनायें जायेंगे।
- अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर Leopard Conservation Reserves तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्रा में Leopard Safari प्रारम्भ की जायेगी।

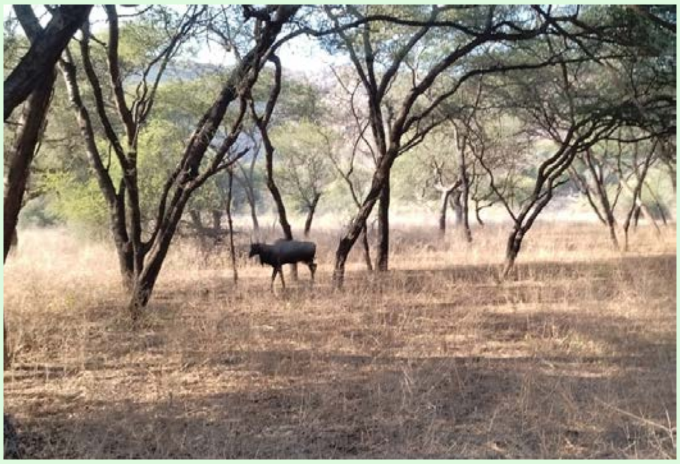

- प्रदेश में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निषिद्ध करने तथा नयी तकनीक के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान व्हीकल सक्रेप पॉलिसी लायी जाएगी।
- वेस्ट रीयूज और रिसायकिल कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित करने, सर्कुलर इकॉनॉमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर वेस्ट टू वैल्थ पार्क्स (सर्कुलर्टी पार्क्स) स्थापित किये जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती खड़ी हो गयी है। इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए 'बर्तन बैंक' बनाया जाएगा। इस हेतु प्रथम चरण में, एक हजार पंचायतों को एक-एक लाख रुपये के बर्तन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

7. Clean Tech Development :

- पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विषयों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु 250 करोड़ रुपये की राशि से क्लीन एण्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- केन्द्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एण्ड ग्रीन-इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा।

8. Green Audit :

- प्रदेश को 'हरित राजस्थान' बनाये रखने हेतु सतत् प्रगति हो, इस हेतु आगामी वर्ष सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से "ग्रीन ऑडिट" कराने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

9. Capacity Building–Education, Skilling :

- राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के इम्पलीमेंटेशन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेकशन एण्ड एक्सीलरेशन सेंटर्स (एसडीजीसीएसी)स्थापित किया जायेगा।
- हमारी नयी पीढ़ी सतत विकास एवं ग्रीन ग्रोथ के सिद्धान्तों को आत्मसात् कर आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में नये विषय प्रारम्भ करते हुए सर्टिफिकेशन कोर्सेस भी उपलब्ध करवाये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

10. Green Funding :

- स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को ग्रीन ग्रोथ सम्बन्धी परियोजनाओं एवं गतिविधियों के क्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, राजकीय परियोजनाओं के लिए ग्रीन फण्ड्स एवं इन्सट्रूमेंट्स को लीवरेज भी किया जायेगा।
- प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के सम्बन्ध में सतत एवं पर्यावरण मित्र समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फण्ड स्थापित किया जाएगा।
- अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाये रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना' शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत जैव विविधता को बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे चैक डैम्स का निर्माण तथा स्थानीय औषधीय पौधों के विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

अन्नदाता की उन्नति समृद्धि की गारंटी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि हस्तान्तरित की गयी।

बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देशभर में 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 वर्ष पहले शुरू की गई थी। अब तक 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना भी शुरू की गई जिससे आपदा के समय किसानों को बीमा क्लेम वितरित किए गए।

इस अवसर जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कृषक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को चैक वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। उन्होंने कृषि संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसान कल्याण और उत्थान के संकल्प को पूरा करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों-पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत समारोह में प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि यह समारोह प्रधानमंत्री के किसानों को खुशहाल बनाने के संकल्प और समर्पण की एक मिसाल है। देश को प्रधानमंत्री की गारंटी पर पूरा भरोसा है।

श्री शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34 हजार सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के लिए अनुदान के प्रावधान, आगामी वित्त वर्ष में 25 हजार फार्म पौंड, 10 हजार डिग्गी, 50 हजार सौर पंप संयंत्र तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान किए गए हैं। इन योजनाओं से प्रदेश के 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 70 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने इस बजट में अन्नदाता को संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने की घोषणा की है। अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगभग 46 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारी सरकार द्वारा योजना के तहत लगभग 3100 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं।

श्री अन्न बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम, किसानों को हो रहा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान श्रीअन्न बाजरे के उत्पादन में देशभर में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसके उत्पादन में किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा मां-बाड़ी केंद्रों में पायलट आधार पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद तथा हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन, ढाई लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, आगामी 2 वर्षों में शेष रहे ढाई हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस के साथ ही 8 नए जिलों में केवीएसएस की स्थापना भी की जाएगी।

महाकुंभ Mela 2025

संगम का स्नान सनातन का मान

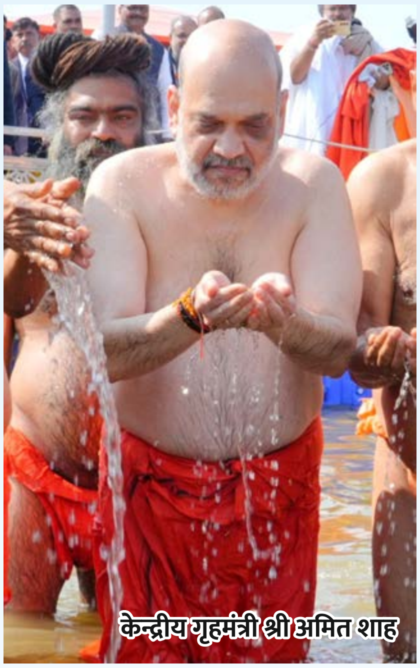
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी

"प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा-अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर-हर गंगे!"

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

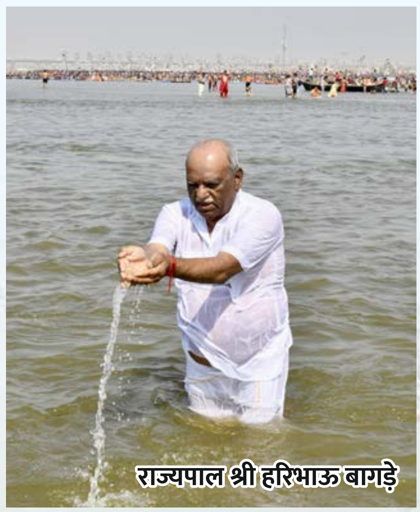
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े

प्रयागराज में 144 वर्षों बाद आयोजित महाकुंभ आस्था के प्रतीक के रूप में एक नया इतिहास रचने में सफल रहा है। यहां की अद्वितीय पवित्रता और आकर्षण ने लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 फरवरी 2025 को संगम में पवित्र स्नान किया। इसके साथ ही, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी भी महाकुंभ के इस अद्वितीय आयोजन के साक्षी बने। त्रिवेणी संगम में सभी ने आस्था की डुबकी लगाई और देश-प्रदेश की समृद्धि और शांति की विशेष कामना की।

आस्था की भाषा, सर्वहित की अभिलाषा
प्रयागराज के महाकुंभ में राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिपरिषद् के सहयोगियों एवं विधायकों के साथ 8 फरवरी 2025 को प्रयागराज में संगम में स्नान किया एवं जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना की। महाकुम्भ में संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इसमें देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोगराग को दोगुना करते हुए 3 हजार रुपए प्रति मंदिर-प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। महाकुम्भ में दूसरी बार पहुंचे श्री शर्मा ने वहां स्थित राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को भोजन भी वितरित किया।

Butterfly
तितली क्षेत्र
MEWAR BIODIVERSITY PARK
ZONE
UDAIPUR

झीलों के शहर में

तितलियों की झलक

- लेकसिटी में स्थित है प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क
- पर्यटकों के साथ प्रकृति प्रेमियों को लुभा रही रंग-बिरंगी तितलियां
- हर तितली के संरक्षण के लिए विशिष्ट पौधा

– डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक

नैसर्गिक सौंदर्य और अनूठे शिल्प-स्थापत्य के कारण विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली झीलों की नगरी उदयपुर के आंचल में राजस्थान के पहले बटरफ्लाई पार्क की सौगात भी है। सघन हरीतिमा के मध्य शहर के अंबेरी में उदयपुर विकास प्राधिकरण के 50 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से वन विभाग द्वारा मेवाड़ जैव विविधता पार्क में स्थापित यह बटरफ्लाई पार्क 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में पाई जाने वाली कुल 189 तितली प्रजातियों में से इस पार्क में 80 प्रजातियों की रंग-बिरंगी तितलियों को देखा जा सकता है। इस बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ लेकसिटीवासियों सहित देश-विदेश के पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय सौगात है।

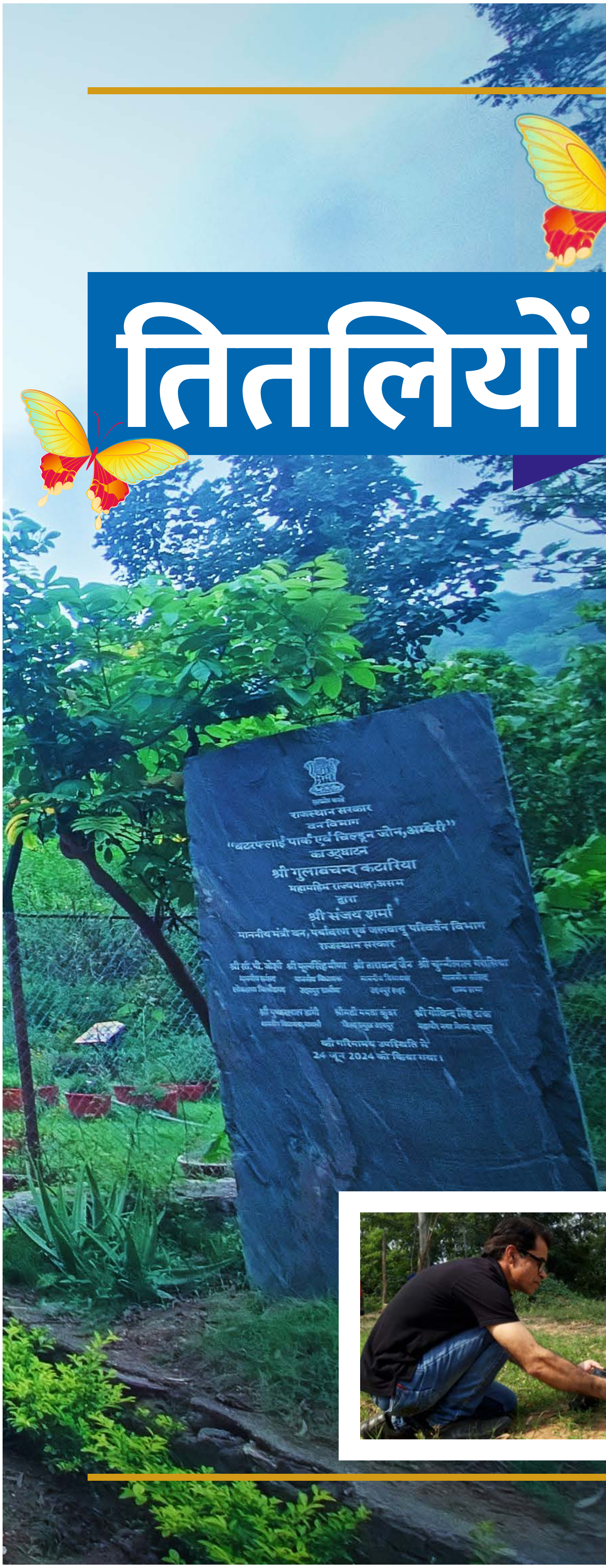

लाईम बटरफ्लाई
Popilio Demoleus

कॉमन जेजेबेल
Delias Eucharis

टाउनी कॉस्टर बटरफ्लाई
Acraea Terpsicore

कॉमन टाईगर बटरफ्लाई
Danaus Genutai

डनाईड एग्फ्लाई
Hypolimnas Misippus

पार्क की तितलियां

इस बटरफ्लाई पार्क में अपने विशिष्ट ज्ञान-कौशल का सहयोग देने वाले तितली विशेषज्ञ सागवाड़ा के निवासी मुकेश पंवार के अनुसार पार्क में तितलियों की लगभग 80 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इनमें कॉमन मोरमोन, लाइम, कॉमन रोज़, टेल्ड जे, प्लेन टाइगर, ब्लू टाइगर, चॉकलेट पेंसी, ब्लू पेंसी, लेमन पेंसी, पिकोक पेंसी, यलो पेंसी, डेनाइड एगफ्लाई, ग्रेट एगफ्लाई, कॉमन इमिग्रंट, मोटल्ड इमिग्रंट, कॉमन ग्रास यलो, व्हाइट ऑरेंज टिप, पायोनियर, गल, सालमोन अरब, कॉमन सिल्वरलाइन, कॉमन शॉट सिल्वरलाइन, प्लंबेअस सिल्वरलाइन, रेड फ्लेश, रेड पीएरोट, कॉमन सेरूलियन, पी ब्लू, फॉरगेट मी नोट, ग्रास ज्वैल, जेब्रा ब्लू आदि तितलियों की प्रजातियां आकर्षण का केन्द्र हैं।

5 जोन में बंटा है बटरफ्लाई पार्क

इस पार्क को 5 अलग-अलग जोन में तितलियों की प्रजातियों के परिवार के आधार पर विभक्त किया गया है। संबंधित प्रजातियों की तितलियों के लिए उसी के अनुरूप पेड़-पौधों को उगाया गया है ताकि उन पेड़-पौधों के फूलों से वे अपना भोजन प्राप्त कर सकें और इनकी पत्तियों पर अपने अंडे देकर वंशवृद्धि कर सकें। इन तितलियों की प्रजाति की अवस्थिति की जानकारी देने के लिए प्रजातिवार बनाए गए जोन में तितलियों के नामों की जानकारी फोटो के साथ दी गई है। इसी प्रकार पार्क के प्रवेशद्वार पर ही प्रजातियों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। इस पार्क को आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है और तितली के आकार में क्यारियां बनाई गई हैं और उनमें फूलों वाले पौधे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर बनाए गए आकर्षक ब्रिज, एनीकट, वॉटर हॉल पार्क की सुंदरता को बढ़ाते हैं।

विशिष्ट तितली वाला भारत का पहला पार्क

इस बटरफ्लाई पार्क की खासियत यह है कि इसमें पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति की तितली समूचे भारत भर में सिर्फ इसी पार्क में पाई जाती है और इसकी यह विशेषता समूचे विश्वभर के तितली प्रेमियों को यहां आने पर मजबूर कर रही है। यहां पर पाई जाने वाली यह विशेष प्रजाति की तितली

प्लेन टाईर बटरफ्लाई
Danaus Chrysippus

ब्ल्यू टाईगर बटरफ्लाई
Danaus Limneace

पिकॉक पन्सी बटरफ्लाई
Junonia Almana

ब्ल्यू पन्सी बटरफ्लाई
Junonia Orithya

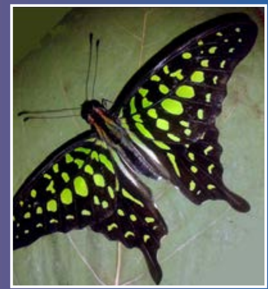
टेल्ड जय बटरफ्लाई
Graphium Agamemnon

"जेब्रा स्किपर" है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम "एर्नस्टा जेब्रा" है। इस तितली का जीवन चक्र अर्थात अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा फूलों का रस पीने (नेक्टर प्लांट) के सम्बन्ध में विश्व में पहली बार मुकेश पंवार के शोध पर ही रिसर्च पेपर (बायोनॉट दिसंबर 2023) में प्रकाशित किया गया। यह तितली अपने अंडे 'मेलहानिया फुटेपोरेंसिस' नामक पौधे पर देती है। यह वनस्पति संकट ग्रस्त पौधों की सूची में सम्मिलित है तथा बटरफ्लाई पार्क में इस पौधे की उपस्थिति देखी गई है।

भारत में जेब्रा स्किपर तितली की खोज वर्ष 2020 में मुकेश पंवार ने सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में की थी। तब इस तितली का जीनस 'स्पियलिया' था, अतः स्पियलिया जेब्रा के नाम से खोज हुई थी। यह तितली इस पार्क में अगस्त से दिसंबर तक देखी गई है। ऐसे में यह पार्क भारत पहला बटरफ्लाई पार्क होगा जहां इस तितली की उपस्थिति देखी जा सकेगी।

तितलियों के लिए अनुकूल

तितलियों हेतु मुख्य रूप से दो प्रकार के पौधे वांछित हैं। पहले लारवल होस्ट प्लांट (अंडे देने तथा लार्वा के भोजन) तथा दूसरे नेक्टर प्लांट या रस पीने हेतु फूल वाले पौधे। ये दोनों प्रकार के पौधे यहां पर मौजूद हैं। समस्त स्थानीय वनस्पतियों पर अलग-अलग तरह के लार्वा होते हैं। अर्थात सभी तितलियां अपनी प्रजाति के अनुसार निर्धारित पौधे पर ही अंडे देती हैं। अतः प्रत्येक प्रजाति के संरक्षण हेतु भिन्न-भिन्न वनस्पतियों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस बटरफ्लाई पार्क में लार्वा के होस्ट प्लांट्स के रूप में कन्थार, अग्निमंथा, मुंडी व आक की झाड़ियां हैं। छोटी वनस्पतियों में दूब, दुर्वा, सामा, अत्रिलाल, पत्थरफोड़ बूटी, ऊट कटिला, सरपुंखा, जंगली मूंग, भूइनी, गंधी बूटी, खट्टी बूटी, चित्रक, लूनीआ आदि हैं। वृक्षों मे अमलतास, मीठी इमली,खट्टी इमली बबूल, रोंज, पलाश, करीपत्ता, नींबू वर्गीय पेड़, अशोक, खजूर, सीताफल, बिल्व आदि, बेल वर्ग मे राखी बेल, ड्रेगिया वेलुबीलिस, ईश्वरी, आदि हैं। नेक्टर के रूप में पौधो में भृंगराज, चिरचिटा, चित्रक, जंगी गोबी, गेंदा, सहदेवी, द्रोण पुष्पी, बहुफली, पुनर्नवा, ब्राम्ही, कंघी, गरखा, मयूरशिखा आदि हैं।

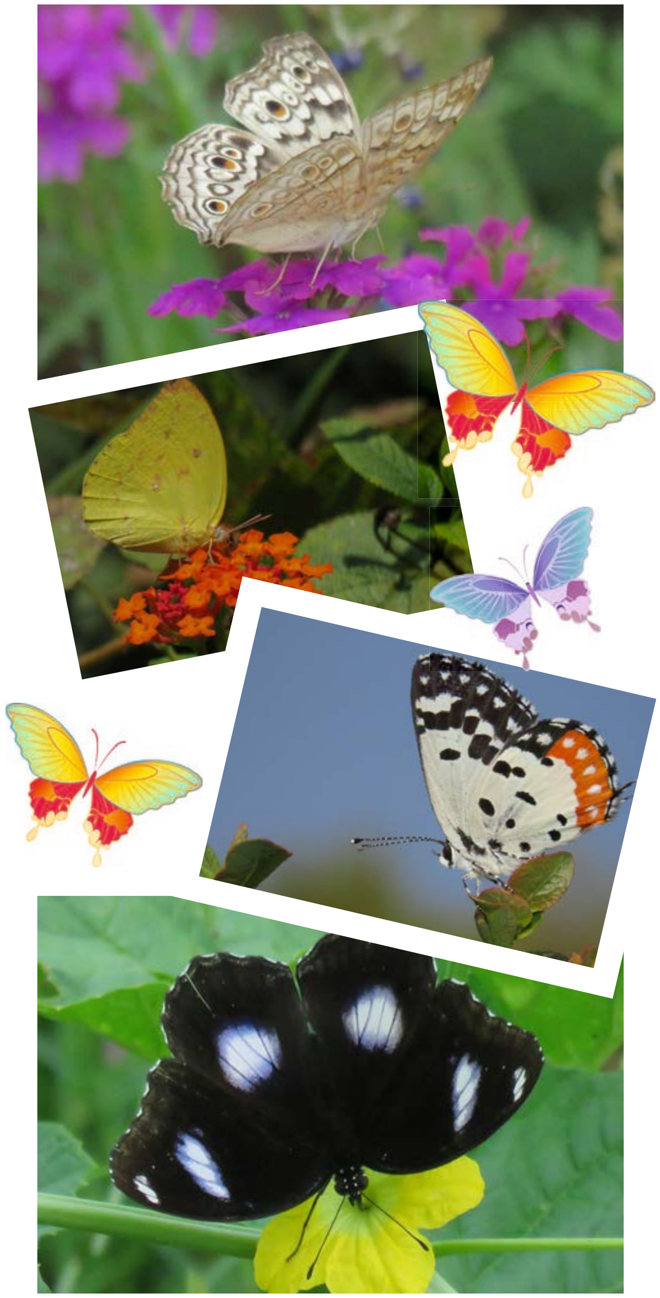

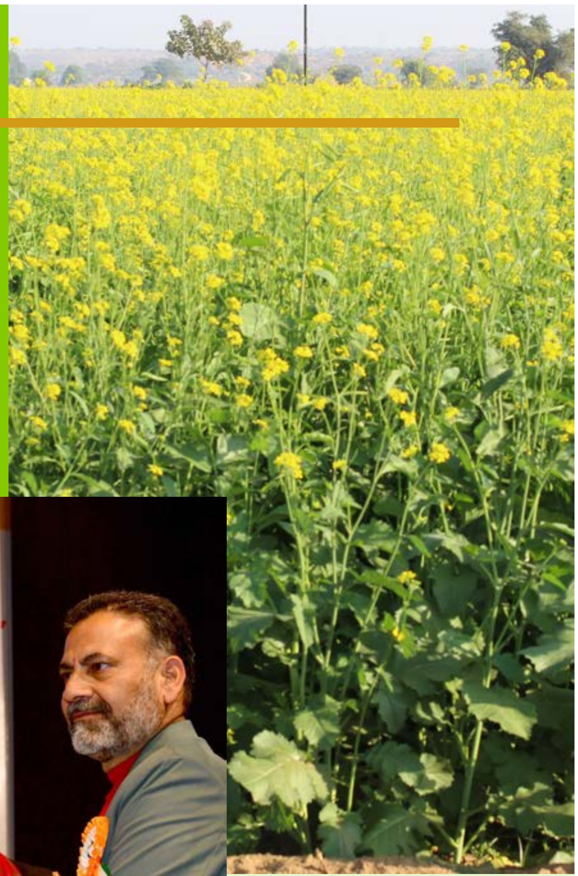

एग्रीस्टेक योजना

डेटा करेगा निहाल किसान होंगे और खुशहाल

- किसानों को मिल रही डिजिटल पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एग्रीस्टेक योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में "फार्मर रजिस्ट्री अभियान" के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन 5 फरवरी 2025 से प्रारम्भ हुआ। राज्य सरकार द्वारा गत 13 दिसम्बर को अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में एग्रीस्टेक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

इन शिविरों में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जा रही है। एग्रीस्टेक भारत में कृषि में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और डेटा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर परिणामों और परिणामों को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा डिजिटल फाउंडेशन है। यह उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा को एक साथ लाने और इस डेटा को उन हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है ताकि वे डेटा का उपयोग कर नई सेवाएं बना सकें। एग्रीस्टैक का उद्देश्य सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभ योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करने की विधि को आसान बनाना है।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री?

फार्मर रजिस्ट्री, एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। इसके अन्तर्गत कृषक विवरण (कृषक का जनसांख्यिकीय विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखण्ड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि) को डिजिटल इंफास्ट्रक्चर में संकलित किया जाकर, प्रदेश के प्रत्येक किसान को "आधार" आधारित एक 11 अंकों की एक यूनीक आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) आवंटित की जा रही है, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। इस हेतु मोबाइल एप/वेबसाइट द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के स्वामित्व वाले सभी खसरों को सम्मिलित करते हुए कृषक के "आधार" से लिंक कराया जायेगा, इसके बाद कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए ई-हस्ताक्षर की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्यों आवश्यक है फार्मर रजिस्ट्री ?

भविष्य में पीएम / सीएम किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। इसी के साथ राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरणकरण एवं क्रय-विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी जरूरी होगी।

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को लाभ

- किसान आईडी (बिना अतिरिक्त दस्तावेज) के माध्यम से सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक किसान की पहुंच आसान हो सकेगी।
- पात्र किसान का पीएम-किसान, सीएम-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना सम्भव होगा।
- किसानों को केसीसी ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा।
- किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों व अन्य योजनाओं में त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) खरीद संभव हो सकेगी।
- किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा।
- किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा।
- किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
- सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी।

कृषि भूमि से संबंधित व्यक्ति ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को महज अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर वाला फोन और नवीनतम जमाबंदी लेकर शिविर में आना होगा। अपनी ग्राम पंचायत में शिविर कार्यक्रम की जानकारी www.rjfrc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। किसान आईडी डिजिटली सत्यापन योग्य पहचान है, जिसे www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए पटवारी, भू-अभि. निरीक्षक या तहसीलदार से सम्पर्क किया जा सकता है। इस हेतु मोबाइल एप/वेबसाइट द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के स्वामित्व वाले सभी खसरों को सम्मिलित करते हुए कृषक के "आधार" से लिंक कराया जाएगा, तत्पश्चात कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए ई-हस्ताक्षर की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

नाम बदला, मिली असली पहचान

सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोनेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर में श्री जगदीश सैनी ने उपखण्ड अधिकारी को बताया कि उसकी कृषि भूमि की जमाबंदी में गत कई दशकों से नाम बाबूलाल सैनी दर्ज होने के कारण वह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं से वंचित है। इस पर तत्काल श्री जगदीश सैनी से नाम शुद्धिकरण का फॉर्म भरवाकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में बाबूलाल सैनी से जगदीश सैनी दर्ज किया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

इस व्यवस्था के तहत श्री जगदीश सैनी को 11 अंको की आधार से जुड़ी फार्मर आईडी मिली है। उसके भू-अभिलेख में स्वतः अपडेशन होने से अब उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपदा प्रबंधन के तहत सहायता, कृषि ऋण, फसल बीमा, फसल सर्वे, स्वामित्व हस्तातंरण, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद व अन्य प्रकार के ऋणों का लाभ मिल सकेगा जिससे वह कई दशकों से वंचित था।

उसने इस प्रकार के किसान हितैषी शिविर आयोजित करने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजू सपेरा को मिला मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र

सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोनेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ।

यह शिविर न सिर्फ किसान हितैषी बल्कि जनकल्याणकारी शिविर है, साबित हो रहे हैं। राजू सपेरा के घुमंतू जाति का होने के कारण उसका व उसके परिवार का न तो मूल निवास प्रमाण पत्र बना था न ही जाति प्रमाण पत्र। इस कारण वे अभी तक केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। इस शिविर में पीड़ा व्यक्त करने पर तत्काल आवेदन भरवाकर उसका व उसके परिजनों के मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवाये गए। उसे जब इनके लाभों के बारे में बताया गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आये। उसने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि अब उसे राज्य सरकार की मंशानुसार आवासीय भू-खण्ड का पट्टा मिल सकेगा, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि सहित उसके बच्चे को छात्रवृत्ति व सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

6000 से अधिक वरिष्ठ जन करेंगे हवाई यात्रा

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

- फरवरी 2025 तक 22 हजार से अधिक तीर्थ यात्रियों ने लिया लाभ
- वरिष्ठजनों की आस्था व आराध्य के दर्शनों को तृप्त कर रही योजना
- 64 फ्लाइट व 27 रेलगाडियों के माध्यम से किए तीर्थों के दर्शन
- वर्ष 2025-26 के बजट में घोषणा- 50 हजार को वातानुकूलित ट्रेनों से तीर्थ दर्शन

- विनोद मोलपरिया, सहायक निदेशक

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना प्रदेश के बुजुर्गों के लिए अपने आराध्य और तीर्थ दर्शन का एक सरल और सुलभ माध्यम बन रही है। दिनों दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार वरिष्ठजन की तीर्थ यात्रा को आरामदायक और निर्विघ्न बनाने के लिए प्रयासरत है।

इन तीर्थ स्थलों की कराई यात्रा

प्रदेश सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना- 2024 के अन्तर्गत रामेश्वरम्, हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या, तिरूपति, गंगासागर, कामाख्या, जगन्नाथपुरी तीर्थों की यात्रा निःशुल्क करवाई जा रही है। इस योजना में हवाई यात्रा के माध्यम से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ तीर्थ की भी यात्रा करवाई जा रही है।

22 हजार से अधिक को मिला योजना का लाभ

देवस्थान आयुक्त वासुदेव मालावत के अनुसार कि रामेश्वरम तीर्थ के लिए संचालित 9 रेलगाडियों के माध्यम से 7146, हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या

के लिए संचालित 12 रेलगाड़ियों के माध्यम से 8768, तिरूपति के लिए 2 रेलगाड़ियों द्वारा 1554, गंगासागर के लिए एक रेल द्वारा 807, कामाख्या के लिए एक रेल द्वारा 770 एवं जगन्नाथपुरी के लिए 2 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1471 सहित कुल 27 रेलगाड़ियों द्वारा 20 हजार 516 वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थ एवं अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ लिया है। इसी क्रम में तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू (नेपाल) के लिए 64 फ्लाइट के माध्यम से 1606 यात्रियों ने तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। रेल व हवाई यात्रा के माध्यम से 22 हजार 122 यात्री निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर चुके हैं।

उदयपुर संभाग से 2359 ने की यात्रा

देवस्थान अतिरिक्त आयुक्त श्री अशोक कुमार के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2024 के तहत अब तक उदयपुर संभाग से रेल के माध्यम से हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या 1854, गंगासागर-कोलकाता 204 एवं कामाख्या 226 सहित 2 हजार 284 यात्रियों ने तीर्थ यात्रा की है। इसी क्रम में हवाई यात्रा द्वारा 75 यात्रियों ने तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। संभाग से 2359 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कर चुके हैं।

योजना का उद्देश्य

प्रदेश में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एक बार देश व देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने के लिए राजकीय सुविधा व सहायता प्रदान करना है।

यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए पात्र व्यक्ति को देवस्थान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिये लिंक के माध्यम से आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नी का जनाधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदक अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थलों को वरीयता क्रम में अंकित कर सकता है।

बजट 2025-26 में 6 हजार को हवाई यात्रा की सुविधा

राज्य विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा एवं 50 हजार वरिष्ठजन को वातानुकूलित ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई है।

नशा मुक्ति की राह पर हनुमानगढ़

'नशे के जीवन' से अच्छा जीवन का नशा

'मानस' की पहल, मानस का भला

-प्रशासन के सकारात्मक अभियान से जिले में आने लगा बदलाव

- राजपाल लंबोरिया, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

प्रदेश का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा तथा पंजाब का सीमावर्ती जिला है। इस कृषि प्रधान जिले में पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति मिश्रित है। घग्घर नदी के आस-पास का क्षेत्र होने से अधिकतर भूमि सिंचित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर ने क्षेत्र को और अधिक समृद्धशाली बना दिया है।

सीमावर्ती जिला होने, आय के बेहतर स्रोत और मिश्रित संस्कृति के जहां एक और सम्पन्नता आई है वहीं दुष्प्रभाव के रूप में जिले में नशे की जड़े फैलती जा रही थीं।

एक वक्त ऐसा भी आया जब नशे की बढ़ती प्रवृति नासूर बनकर धीरे-धीरे दीमक की तरह घर-परिवार और पीढ़ियों को खत्म कर रही थी। समाचार पत्रों में केवल नशा और नशे से होने वाली अकाल मौतें ही हैडलाइन बनने लगी थीं। जिले में प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ आमजन ने भी नशा मुक्ति को लेकर भरसक प्रयास किए, लेकिन विस्तृत कार्ययोजना के अभाव में प्रयास धरातल पर उतर नहीं पाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जिले में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की बजट घोषणा के बाद से जिला प्रशासन और आमजन के प्रयासों से नशा मुक्ति मुहिम जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

इसी बीच राज्य सरकार के प्रयासों से जिला कलेक्टर श्री काना राम की अगुवाई में सरकार ने विस्तृत अध्ययन और उच्चस्तरीय मार्गदर्शन से कार्ययोजना तैयार की। एक-एक व्यक्ति की भूमिका तय करते हुए जनसहभागिता से मई, 2024 में नशे की प्रवृति को रोकने के लिए "नशा मुक्त मानस अभियान" की पहल हुई। हर विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई और सबसे पहले अपने-अपने विभागों को नशा मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ी गई।

इसे सामूहिक प्रयासों का उत्साह ही कहेंगे कि एक के बाद एक विभागों ने अपने कार्यालयी कामकाज से लेकर दैनिक जीवन में भी "नशा मुक्त मानस अभियान" को संजो लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, औषधि नियंत्रण, खेल, सूचना एवं जनसम्पर्क एवं शिक्षा सहित

विभिन्न विभागों को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई।

विस्तृत कार्ययोजना तैयार होने के बाद 26 जून, 2024 को इस कार्ययोजना को लागू किया गया। जिले के सभी विभागों और स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। धीरे-धीरे कार्ययोजना अनुसार ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होने लगे। नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए 4 चरणों में कार्यवाही की योजना बनाई गई।

प्रथम चरण

पहले चरण में प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान को रखा गया। इसके अनुसार प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों में माह के अंतिम शनिवार को "नशा मुक्त मानस अभियान" के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक संस्थान के हर विद्यार्थी और शिक्षक की भागीदारी सुनिश्चित हुई। जिले में हो रहे प्रत्येक कार्यक्रम में आमजन को नशा नहीं करने की शपथ दिलाना शुरू किया गया। इसी के परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभी तक एक लाख से भी अधिक जिलेवासियों ने ई-शपथ ली है, जो निरन्तर जारी है। यह आंकड़ा पूरे देश में किसी भी जिले में ऑनलाइन ली गई शपथ में सर्वाधिक है।

द्वितीय चरण

दूसरे चरण में उपचार एवं काउंसलिंग में नशे के आदी व्यक्तियों का सर्वे कर आंकड़े जुटाए गए। शिविरों के जरिए नशे के आदी व्यक्तियों की काउंसलिंग शुरू की गई। शिविर लगाकर फॉलोअप किया गया। जिला स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्तर पर हैल्पलाइन नंबर शुरू किए गए। यहां पहचान गोपनीय रखते हुए आमजन को नशा छोड़ने व चिकित्सा के लिए परामर्श दिया जा रहा है। अब तो नशे और अवैध गतिविधियों की सूचना भी आमजन हैल्पलाइन नंबर के जरिए आगे बढ़कर दे रहे हैं।

तृतीय चरण

तीसरे चरण में नशा नियंत्रण की कार्यवाही शुरू की गई। इसमें औषधि नियंत्रण विभागीय टीम ने मेडिकल दवाओं की दुकानों पर निरीक्षण गतिविधियों को बढ़ाते हुए अवैध बिक्री पर लगाम लगाई। दवा विक्रेताओं पर ऑनलाइन निगरानी तक शुरू की गई, जिसके लिए 5 अक्टूबर, 2024 को "मानस ई- आरोग्य पोर्टल" की शुरुआत की। वर्तमान में 20 क्लिनिक, 25 मनोचिकित्सक, लगभग 15 हजार मरीज इसे सक्रिय रूप से उपयोग में ले रहे हैं। इससे नशे में उपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री पर लगाम लगी है। नशे में उपयोग होने की आशंका वाली दवाओं को प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया। वहीं, पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाहियां की गई। नशा सामग्री से अर्जित अवैध सम्पतियों को फ्रीज़ और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसी कड़ी में अब पुलिस द्वारा अपने 16 थानों के तहत 16 गांवों को गोद लेते हुए उन्हें नशा मुक्त बनाने की अनूठी पहल की गई।

चतुर्थ चरण

चौथे चरण में युवाओं को व्यस्त और स्वस्थ रखने के लिए "मानस खेल अभियान" का शुभारम्भ किया गया। गांवों में प्रतिदिन खेलों के आयोजन तथा प्रतिमाह जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। इसके जरिए युवाओं को नशे की लत से जुड़ने से रोका जा रहा है। खेलों के लिए खेल स्टेडियम विकसित करने के लिए 62 ग्राम पंचायतों में 729 लाख रूपए के कार्य स्वीकृत किए गए।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्ययोजना के धरातल पर उतरते ही समाचार पत्रों की हैडलाइन और आमजन की मानसिकता दोनों में बदलाव आने लगा है। गांवों में स्काउट, पर्यावरण, खेलकूद की तरह नशा मुक्त क्लब बनने शुरू हो गए हैं, जो कि नशा मुक्ति अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी सार्थक प्रयासों का ही सफल परिणाम है कि अब आमजन की मानसिकता बदली है। लोग नशे के विरूद्ध लामबंद होने लगे हैं।

अब हनुमानगढ़ के समाचार पत्रों में नशे से मौत, बिखरते घर-परिवार और दुर्घटनाएं की सुर्खियां कम हो रही है। अब नशा मुक्त जिले की संकल्पना साकार करने के लिए आमजन की जागरूकता, संगोष्ठियों, चिकित्सकीय शिविर, प्रशासन की सख्त कार्यवाही, स्कूल-कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यशालाओं-प्रतियोगिताओं की ही खबरें पढ़ी जा रही है।

त्वरित न्याय: सुशासन का पर्याय

जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अच्छा वकील कानून का ज्ञाता होने के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की आवाज भी बनता है। वकील का पेशा गरीब और वंचित वर्ग की सेवा के लिए बड़ा अवसर होता है। उन्होंने कहा कि इस पेशे ने अनेक महान राष्ट्र निर्माता दिए हैं। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब अंबेडकर भी वकील थे। इस संविधान के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है।

दीक्षांत समारोह में श्री शर्मा ने विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि एवं विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस डिग्री को अपनी उपलब्धि के साथ एक महती जिम्मेदारी भी मानें। समाज में न्याय की रक्षा और प्रसार के लिए विद्यार्थियों को काम करना है। इसके लिए कानून की शिक्षा के साथ गहरी समझ, संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित न रहें। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का उपयोग बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश-प्रदेश बनाने में करें।

तीन नए आपराधिक कानूनों से की गई शीघ्र न्याय की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इनके माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी प्रदेश में नए कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और इनका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

हमारी न्याय व्यवस्था की हजारों वर्षों से दुनिया में विशिष्ट पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखती थी। इसका मूल यह था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं हो और सभी को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन हो रहे हैं तथा नए कानून भी बन रहे हैं।

जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का देश में खास स्थान

श्री शर्मा ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिन एक यादगार क्षण है। इस विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों ने जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है, वह उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा तथा विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलावों का वाहक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय देश में एक खास स्थान रखता है। कानून के क्षेत्र में यहां के विद्यार्थियों ने देश और विदेश में पहचान बनाई है।

न्यायिक कार्यालय भवनों एवं आवास के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 4 अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट), 3 विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायिक कार्यालय भवनों एवं आवास हेतु 350 करोड़ रुपये, नवीन न्याय संहिताओं की आवश्यकताओं हेतु कम्प्यूटर, कैमरों सहित विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अपराधों की रोकथाम हेतु 'सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम' की स्थापना के लिए भी 350 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

प्रदेश में पारदर्शिता से हो रही भर्तियां, युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं तथा पांच वर्ष में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी और 1.50 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए 'राजस्थान रोजगार नीति-2025' भी लाई जा रही है।

उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न नवीन जर्नल्स का विमोचन किया एवं ई-मूट कोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कर विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर 24 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा एवं त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। साथ ही, गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई प्रावधान भी किए गए हैं।

श्री शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं पदोन्नति करने के निर्देश दिए ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रदेश के हर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का भी पूर्ण विवरण तैयार करे ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गृह विभाग से जुड़े शत प्रतिशत कार्मिकों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों से संपत्तियां अर्जित करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां जब्त की जाए जिससे उनके हौंसले पस्त हों। उन्होंने प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लेने एवं ई-सम्मन की प्रभावी तामील कराने के निर्देश दिए ताकि अपराधियों पर सतत् निगरानी के साथ प्रभावी नियंत्रण भी रहे। उन्होंने कहा कि पहली बार अपराध करने वाले को नवीन कानूनों में एक तिहाई सजा पूर्ण होने पर रिहा करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए।

जिला पंच गौरव योजना

विरासत, पर्यावरण के संरक्षण के साथ उन्नति और रोजगार

मनोज कुमार मेहरा, सहायक निदेशक

पंच गौरव अलवर की देश-विदेश में बना रहे विशेष पहचान

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पंच गौरव कार्यक्रम हर जिले में प्रारम्भ किया गया है। इसमें जिले की क्षमता एवं क्षेत्र विशेष में विशिष्टता के आधार पर उत्पादों एवं स्थलों का चयन कर उनके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के माध्यम से जिले को एक मजबूत सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान दिलाई जा रही है।

अलवर जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक पृष्ठभूमियों के साथ-साथ प्राकृतिक संपदा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले के पंच गौरव के रूप में पर्यटन स्थलों में सरिस्का टाइगर रिजर्व, उपज में प्याज, खेल में कुश्ती, उत्पाद में ऑटो कम्पोनेंट व प्रजाति में औषधीय वरदान का खजाना अर्जुन वृक्ष को शामिल किया गया है। जिले के इन पंच गौरवों ने अपनी खूबी के आधार पर देश-दुनिया में अपनी छाप स्थापित अलवर को विशेष पहचान दी है और अब इससे जिले के पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक उन्नति व नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

जिले के पंच गौरव...

एक जिला-एक पर्यटन स्थल :- सरिस्का टाइगर रिजर्व

अलवर-जयपुर मार्ग पर अलवर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित सरिस्का अभयारण्य देशी व विदेशी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। रेलमार्ग, मजबूत सडक नेटवर्क के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाई-वे से देश व प्रदेश की राजधानी के साथ-साथ देशभर से बडी संख्या में सैलानी वर्ष भर यहां आकर जंगल सफारी से नैसर्गिक प्रकृति के नयनाभिराम दृश्य का आनन्द उठाने के साथ टाइगर साइटिंग का रोमांच उठा रहे हैं। यहां धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में ऐतिहासिक पाण्डुपोल हनुमान मंदिर एवं भर्तृहरि महाराज मंदिर अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं जिसमें वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का ताता लगा रहता है।

वर्तमान में सरिस्का 42 बाघ-बाघिन व शावकों से आबाद है। बाघ परियोजना क्षेत्र में 1978 ई. में शामिल किए गए इस अभयारण्य में टाइगर के साथ-साथ पैंथर, हाइना, गीदड, चीतल, सांभर, हरिण, नीलगाय, जंगली सूअर तथा अन्य वन्य जीवों का स्वच्छंद विचरण देखने के लिए देशी और विदेशी सैलानी वर्ष पर्यन्त आते रहते हैं। यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कांकवाड़ी का प्रसिद्ध किला भी इसी क्षेत्र में है। इस अभयारण्य के पास ही सिलीसेढ़ झील, भानगढ, नीलकंठ महादेव मंदिर, तालवृक्ष जैसे पर्यटन स्थल भी पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

एक जिला - एक उपज :- अलवर की प्याज बेमिसाल

प्याज का सब्जियों में अहम स्थान है। अलवर जिला प्याज के उत्पादन में विशेष स्थान रखता हैं। प्याज की फसल प्रमुख रूप से बीज द्वारा उगाई जाती है परन्तु अलवर जिले में खरीफ व रबी की फसलों के बीच में गंठियों द्वारा प्याज की फसल उगाई जाती हैं। इस प्रकार जिले की गंठिया प्याज कि अपने आपमें विशिष्टता लिए हुए है। इसकी पैदावार से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मजबूती मिलती है। वर्तमान में जिले के मालाखेड़ा, उमरैण, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्याज की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जोड़ा गया है। राज्य सरकार द्वारा एफपीओ को बढ़ावा देकर प्याज प्रसंस्करण की दिशा में कार्य किया जा रहा हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को एफपीओ से जोड़कर उन्हें प्याज प्रसंस्करण यूनिट लगाकर अपनी आमदनी में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक जिला - एक खेल :- अलवर की पहचान कुश्ती

कुश्ती अलवर जिले का प्राचीन एवं परम्परागत खेल रहा हैं। जिलेभर में ग्रामीण क्षेत्र में मेलों में कुश्ती के दंगल लगते हैं। जिसे बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग देखने आते हैं। अलवर के अजरूद्दीन, अनिल कुमार, राहुल व मलखान सिंह जैसे अनेक पहलवानों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर जिले का गौरव बढाया है। हाल ही में अलवर के पहलवान अंकित गुर्जर व लालाराम गुर्जर ने मलेशिया में डेफ एशियन पेसिफिक गेम में कांस्य पदक जीता। इस खेल को बढावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अलवर में महिला कुश्ती अकादमी बनाई जा रही है।

एक - जिला एक उत्पाद :- ऑटो कम्पोनेंट

देश व प्रदेश की राजधानी के बीचों-बीच स्थित अलवर जिला औद्योगिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले में पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर शहर एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 160 ऑटो कम्पोनेंट इकाइयां स्थापित हैं इनमें मुख्य रूप से टेफे ट्रेक्टर, अशोका लिलेंड, हरिओम प्रिसीजन, अलाईज प्रा. लि. आदि कम्पनियां ऑटो कम्पोनेंट्स का उत्पादन कर रही हैं। इन इकाइयों में लगभग 7 हजार, 500 लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इन इकाइयों का वार्षिक टर्न ओवर लगभग 10 हजार करोड़ हैं। इन इकाइयों द्वारा हाइड्रोलिक पम्प, एल्यूमिनियम, कास्टिंग, साइड कवर, गेयर बुश, हाइड्रोलिक गियर पम्प, एयर कम्प्रेसर पार्ट्स आदि का निर्माण किया जाता है। इन कंपनियों का उत्पाद यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, तुर्की और दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में निर्यात किया जा रहा है।

एक जिला - एक प्रजाति :- औषधीय वरदान अर्जुन

अलवर में बहुतायत में पाया जाने वाला अर्जुन का वृक्ष औषधीय महत्व के गुण रखता है। यह वृक्ष अलवर के सरिसका वन क्षेत्र के नारायणपुर उपखण्ड में प्रचुरता में देखा जा सकता है। इस का नाम महाभारत कालीन पाण्डु के पुत्र अर्जुन के नाम पर पड़ा है। अर्जुन की छाल हृदयाघात, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अल्सर, मूत्राघात और अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए प्रकृति का वरदान है। हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग द्वारा जिले में बडी संख्या में अर्जुन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही वन क्षेत्र के आसपास के निवासियों को अर्जुन के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

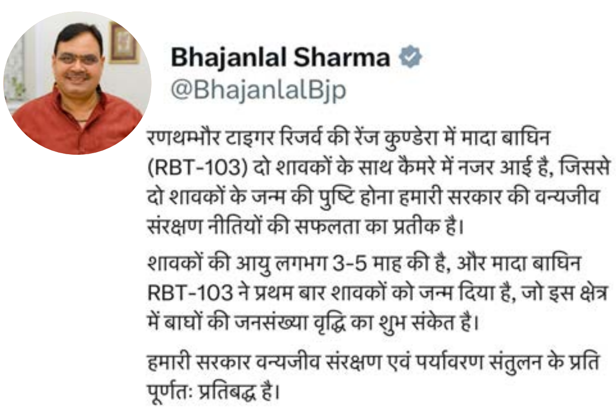

"वाटर विजन 2047" सम्मेलन

जल आत्मनिर्भरता
सुरक्षित भविष्य की प्रेरणादायक यात्रा

झीलों की नगरी उदयपुर में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 18 - 19 फरवरी को दो दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन- "वाटर विजन-2047" आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोडमैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि तथा शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। उन्होंने इस आयोजन के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती-जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है।

जल संरक्षण को विकास एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में "विकसित भारत 2047" के सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के रूप में एक भागीरथी प्रयास किया है। इसका लाभ आज राजस्थान के भी करोड़ों लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार शेष परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को देश के विकास एजेंडे में सर्वाच्च प्राथमिकता दी है तथा इस सबंध में एक अलग से जलशक्ति मंत्रालय भी बनाया, जिससे जल से संबंधित परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है तथा इसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि "कर्मभूमि से मातृभूमि" कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के 60 हजार गांवों में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वैल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए कम पानी में उगने वाली फसलों, शहरी जल प्रबंधन, सीवरेज के पानी के शुद्धिकरण एवं पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जल गुणवत्ता और स्रोतों की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग सहित विभिन्न कदम उठा रही है।

जल प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के विजन पर हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया तथा 12 करोड़ शौचालय बनाए जिससे 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए तथा डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 25 लाख महिलाओं को किट एवं प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह, वर्षा जल संग्रहण के लिए "कैच द रैन" का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी गांवों में भू जल पुर्नभरण के लिए रिचार्ज वैल बनाने में योगदान दे रहे हैं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ओडिशा में से कई बड़ी नदियां बहती हैं, जो जल संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में वर्षा पर्याप्त है, लेकिन वर्षा वितरण में असमानता है। इसलिए जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने बाढ़ नियंत्रण तथा जल संरक्षण को विभिन्न परियोजनाओं में प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी महिला स्वयं सहायता समूह भी भू-जल रिचार्ज करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा का 70 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है तथा अधिकतर जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारी सरकार सिंचाई के प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़े तथा किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सीमित जल संग्रहण क्षमता के कारण सतही जल आधारित सिंचाई परियोजनाओं की संभावना कम है। ऐसे में, वर्षा जल संरक्षण स्ट्रक्चर तथा छोटे सिंचाई के बांधों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन से पूर्व सम्मेलन के प्रतिभागियों के सम्मान में जग मंदिर परिसर में रात्रि भोज दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील के साथ बोट में सवार होकर जग मंदिर पहुंचे। देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए आयोजित अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, जल संसाधन, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मरुभूमि

रंगत धूसर, धरा ऊसर,
जल से सदा की रार।
फिर भी यहां के
खुश नर-नार, उछाह अपार।

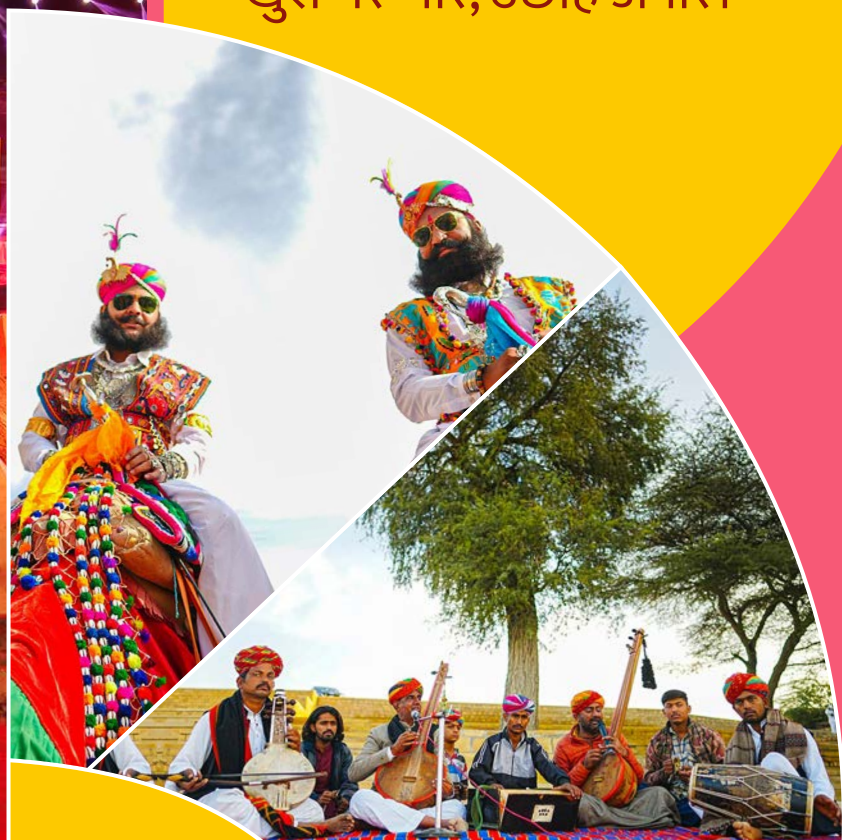

मरु महोत्सव 2025

माही महोत्सव में बरसे अंचल के रस-रंग

- लोकसंस्कृति के मनोहारी आयोजनों की रही धूम

- **कल्पना डिण्डोर,** उप निदेशक

बांसवाड़ा जिले में पिछले दिनों माही अंचल की बहुआयामी लोक संस्कृति और मनोहारी परम्पराओं का दिग्दर्शन कराने वाले 4 दिवसीय परम्परागत माही महोत्सव में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यादगार धूम रही। महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन, नगर परिषद एवं पर्यटन विभाग द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा विकसित राजस्थान के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा लोक सांस्कृतिक परम्पराओं को सुदृढ़ किए जाने की दिशा में बहुआयामी पर्यटन विकास के लिए आंचलिक महोत्सवों को सम्बल दिया जा रहा है। माही महोत्सव के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन विकास और इससे जुड़े आयामों को गति प्राप्त होगी।

भव्य शोभायात्रा में उमड़ा उल्लास का ज्वार

महोत्सव का आगाज भव्य एवं मनोहारी शोभायात्रा से हुआ। शोभायात्रा में सुसज्जित ऊंट, अश्व, बालिकाओं की मंगल कलश यात्रा, लोक कलाकारों की सांगीतिक नृत्य एवं गायन प्रस्तुतियों, उत्साही लोगों की आत्मीय भागीदारी से यह दृश्य देखते ही बनता था। कुशलबाग मैदान से आरंभ हुई शोभायात्रा का नगर के मुख्य मार्गों पर जमा शहरवासियों ने पुष्पवृष्टि से शानदार स्वागत किया। गाजे-बाजे के साथ निकली शोभायात्रा में कलाकारों के समूहों ने मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं। शोभायात्रा में पर्यटन विभाग के लोक कलाकारों, विभिन्न पंचायत समिति के स्थानीय कलाकारों, नगर क्षेत्र की विभिन्न स्कूलों के छात्र - छात्राओं, विभिन्न पंचायत समिति के कलाकारों, विभिन्न समाजों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व वैण्ड वादक दल में पुलिस व स्कूलों के बच्चों ने बैण्ड प्रदर्शन किया।

रन फॉर माही

माही महोत्सव के अन्तर्गत रन फॉर माही का आयोजन किया गया। कुशलबाग मैदान से आरंभ हुई रन डायलाब हनुमान मंदिर पहुंचकर सम्पन्न

हुई। इसमें महिला एवं पुरुषों ने उत्साह से भाग लिया। रन फॉर (महिला वर्ग) में गाइड सविता कटारा-प्रथम एवं गाइड प्रियंका भाभोर- द्वितीय स्थान पर रहीं वहीं पुरुष वर्ग में स्काउट अजित रावत ने प्रथम तथा प्रिन्स ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए।

क्रिकेट मैच

माही महोत्सव के तहत् क्रिकेट मैच का भी आयोजन हुआ। इसमें राजस्व टीम (जिला प्रशासन) की टीम ने पुलिस विभाग की टीम को हराकर खिताब हासिल किया।

माही पूजन, नौकायन प्रतियोगिता

माही महोत्सव की श्रृंखला में रतलाम मार्ग स्थित महाराणा प्रताप सेतु (गेमन पुल) क्षेत्र में माही पूजन में माही मैया के प्रति गहरी आस्था दिखाई दी। इसके साथ ही मीलों तक पसरे जल क्षेत्र में नौकायन प्रतियोगिता आकर्षण का केन्द्र रही।

उत्साही नाविकों ने नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। खेल टीम के निर्देशन में हुई नौकायन प्रतियोगिता में माही की लहरों पर दौड़ती नौकाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरवासी उमड़े और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। नौकायन प्रतियोगिता में 19 नावों में 38 टीमों ने हिस्सा लिया।

ये रहे विजेता

नौकायन प्रतियोगिता में मनीष और दिनेश ने प्रथम, रमेश और विनोद ने द्वितीय एवं राजू और हरीश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सांभर महोत्सव बना दो लाख पावणों का आनन्दोत्सव

हेमन्त सिंह, उप निदेशक

सांभर क्षेत्र के पर्यटन कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग व जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 24 से 28 जनवरी 2025 तक पांच दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन सांभर कस्बे में झपोक झील के किनारे किया गया।

इस पांच दिवसीय महोत्सव के दौरान देसी, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रोमांचक बाईक राइड, फैन्सी पंतगबाजी, पैरा सेलिंग, एटीवी राईड्स, ऊंट सवारी, छायाचित्र प्रदर्शनी, सांभर नमक बनाने की प्रक्रिया देखने हेतु भ्रमण, शानदार व सुन्दर पक्षी देखने के अनुभव के साथ-साथ लोक कलाकारों की आकर्षक व शानदार नृत्य व गायन प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोक कलाकारों की मनमोहक

प्रस्तुतियां, सांभर टाउन हेरिटेज वॉक, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता, घुड़सवारी, ऊंटसवारी और ऊंटगाड़ी की सवारी सहित आकाशीय सितारों का अवलोकन और एस्ट्रो टूरिज्म ने भी पर्यटकों को आकर्षित किया।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पांच दिवसीय सांभर महोत्सव में देशी-विदेशी सैलानियों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू कराया गया। उन्होंने बताया कि सांभर की सॉल्ट लेक अब प्री-वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव के दौरान कई भव्य आयोजन हुए, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए।

इस अविस्मरणीय, मनमोहक सांभरलेक लोक महोत्सव में दो लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति रही। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी की अब प्रदेश में सांभरलेक भी नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर सामने आने लगा है।

डीडवाना-कुचामन में विकास कार्य

100 करोड़

युवाओं की उम्मीदों को

पूरा कर रही सरकार

राज्य सरकार युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में विकास और सेवा की भावना के साथ राज्य सरकार हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली और उन्नति सुनिश्चित कर रही है।

यह बात मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों कुचामनसिटी में स्व. श्री भंवराराम कड़वा के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पूर्व सरपंच व जनसेवी स्व. श्री भंवराराम कड़वा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डीडवाना-कुचामन की धरा संतों और समाजसेवियों की भूमि है। यहां जन्म लेने वाले स्व. श्री भंवराराम जी का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा तथा उनके द्वारा पल्लवित श्री नारायण नर सेवा संस्थान आज भी समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

किसान कल्याण का रखा ध्यान

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास एवं किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रथम वर्ष में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। राज्य में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में राम जलसेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी), शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता, दक्षिणी राजस्थान के लिए देवास परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया गया है। साथ ही आई.जी.एन.पी एवं माही परियोजना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान जल उपलब्धता के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनेगा।

वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों का दर्द समझती है और उन्हें सस्ती एवं सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्य

सरकार ने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने (बजट 2025-26 में इसे बढाकर 9 हजार रुपए कर दिया गया है।), गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने (नवीन बजट में इसे और बढा दिया गया है) के साथ ही पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एवं मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत की है।

एक साल में 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन

श्री शर्मा ने कहा कि सरकार हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार के आग्रह पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया है।

60 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां, 81 हजार पदों का परीक्षा कैलेण्डर जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में अब तक लगभग 60 हजार सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी है और जुलाई माह तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। साथ ही, नए साल के आरंभ के साथ हमने वर्ष 2025 में 81 हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके जरिये प्रदेश में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं।

एक हजार नए आंगनबाड़ी केन्द्र

श्री शर्मा ने कहा कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है। प्रदेश में एक हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराने के लिए अमृत आहार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अन्त्योदय के संकल्प के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आस-पास के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं।

डीडवाना-कुचामन में 100 करोड़ रूपये के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डीडवाना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर लागू कर रही है। डीडवाना-कुचामन जिले में लगभग 100 करोड़ रूपये के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। साथ ही, डीडवाना-कुचामन जिले की बजट घोषणाओं में से 78 प्रतिशत घोषणाओं में स्वीकृति जारी करने के साथ ही भूमि आवंटन से संबंधित सभी कार्यों में 100 प्रतिशत भूखण्ड आवंटित कर दिए गए हैं। बजट घोषणाओं की अनुपालना में छोटी खाटू पर आर.ओ.बी निर्माण की डी.पी.आर का कार्य तथा 5 करोड़ रुपये की लागत से नावां शहर की विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगतिरत है। इसी तरह मारोठ में सहायक अभियंता (विद्युत) एवं नावां में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) कार्यालय खोलने, भांवता में 132 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटन, डीडवाना शहर में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश, भूणी, आगुंता एवं कुचामन सिटी में 33 केवी जीएसएस के लिए भूमि आवंटन भी कर दिया गया है।

श्री शर्मा ने कहा कि डीडवाना कुचामन के शिवदानपुरा में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के साथ ही जसवंतगढ़ (लाडनूं) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व खोरंडी उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन किया गया है। इसी तरह डीडवाना जिला चिकित्सालय की बेड क्षमता 200 से बढ़ाकर 300 तथा कुचामन जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट का संचालन एवं मौलासर स्वास्थ्य केन्द्र क्षमता को 30 से 50 बेड किये जाने के साथ ही कुचामनसिटी में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। वहीं जिले में नवीनतम टेक्नोलॉजी आधारित ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के संचालन हेतु निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भगवान देवनारायण जी का 1113वीं जयंती समारोह

राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

बिड़ला सभागार में देवनारायण जी की 1113वीं जयंती (4 फरवरी) के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गुर्जर समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही, समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज समर्पण से कार्य कर देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। समाज ने न केवल युद्ध में अपना कौशल दिखाया अपितु देश की सामाजिक संस्कृति को संजोए रखने का भी कार्य किया है।

विकास के पथ पर विरासत का भी संरक्षण- मुख्यमंत्री

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप हमारी सरकार विकास कार्यो के साथ-साथ विरासत संरक्षण का कार्य कर रही है। खाटूश्याम मंदिर में कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और पूंछरी का लौठा का पुनर्विकास किया जा रहा है। साथ ही, कैमरी के जगदीश मंदिर में कृष्णगमन पथ के तहत तथा देवनारायण जी मंदिर आसींद (भीलवाड़ा) में विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रयागराज में महाकुंभ मेले में बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं।

पशुपालकों के कल्याण के लिए किए नीतिगत निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में पशुपालकों एवं कृषकों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुचामन सिटी-डीडवाना, बाली (पाली), कोटपूतली, पसोपा (नगर) में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। नसीराबाद में देवनारायण बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, उसे सभी अनुभव कर रहे हैं। देश में गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास योजनाएं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव देश के हर नागरिक ने देखा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री उनकी बात को चरितार्थ कर रहे हैं।

हमारा लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का उत्थान

धाकड़ समाज का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन

कोटा के दशहरा मैदान में श्री धाकड़ महासभा द्वारा आयोजित 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धाकड़ समाज देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला समाज है, इस समाज का इतिहास परिश्रम, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि श्री धरणीधर भगवान के उपासक धाकड़ समाज के युवा अब केवल कृषि कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्यमिता के जरिए उद्योग क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, जो कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धाकड़ समाज के ग्रामीण पृष्ठभूमि के होनहार बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रावास हेतु जयपुर में भूमि आवंटित करेगी।

राज्य सरकार युवाओं को समय पर दे रही नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में लगभग 60 हजार युवाओं को नौकरी दी है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 81 हजार भर्तियों का परीक्षा कैलेण्डर जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का मनोबल टूट गया था, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम कस दी है।

किसानों को दो हजार रुपये की अतिरिक्त सम्मान निधि

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पानी और बिजली की बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मिल रही 6 हजार रुपये की सम्मान राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी दो हजार रूपये की सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के ऐसे साढ़े सात लाख किसानों को सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया है जिन्हें नामांतरण के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रखा गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के हित में गेंहू की एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

डबल इंजन की सरकार विकास के लिए कृतसंकल्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पानी पहुंचाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में प्रदेश का तेजी से विकास करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार जातियां बतायी हैं। हमारा लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं श्रमिकों का उत्थान करना है तथा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

धाकड़ समाज कृषि नवाचार में बन रहा प्रेरणा - लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि यदि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, तो किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि धाकड़ समाज की पहचान कठिन परिश्रम, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव से बनी है। यह समाज तपती धूप और ठिठुरती ठंड में भी खेतों में मेहनत कर अन्न उपजाता है और देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है।

विधानसभा अवलोकन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की।

नेवा सेवा केन्द्र का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने हाल ही में विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र का शुभारम्भ किया। श्री देवनानी ने बताया कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के इस केन्द्र से विधानसभा को पेपरलैस बनाये जाने से संबंधित नेवा मॉडयूल्स का प्रशिक्षण और इससे संबंधित तकनीकी सहायता विधायकगण को उपलब्ध करवाई जायेगी। यह केन्द्र विधायकगण के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी ई-लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की राज्य की विधान सभाओं को डिजिटल बनाये जाने के लिए नेवा एप्लीकेशन का संचालन राजस्थान विधानसभा में भी किया जा रहा है।

शादी के एक वर्ष तक कर सकेंगे आवेदन

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि छह माह को बढ़ाकर 1 वर्ष किए जाने का सर्कुलर जारी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा महिला खिलाडियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

RISING RAJASTHAN

सपना होगा साकार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नया राजस्थान, बदलता राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

श्री शर्मा ने यह बात जयपुर शहर में एक होटल में जेनपैक्ट ग्लोबल मीट में अपने सम्बोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जेनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

आईवाईसी-राज्य स्तरीय एपेक्स समिति का गठन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होगे समिति के अध्यक्ष

"अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष— 2025" के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में "आईवाईसी-राज्य एपेक्स समिति" का गठन किया गया है।इस समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष— 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।यह समिति राज्य में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में होंगे विकास कार्य

किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट, भवानीमण्डी, देवली एवं कोटपूतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर एवं पूगल रोड (अनाज), बीकानेर, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं पदमपुर में सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

हिन्दी हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक

केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी है।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने अपने संबोधन में कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान-सम्मान रखते हुए हिन्दी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयास करना होगा। राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि भाषा मानव समाज और देश की अंतः शक्ति है।

सशक्त पंचायतीराज राज्य सरकार की प्राथमिकता

सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायतीराज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने कहा कि सरपंचों के हाथों में गांवों के विकास की बागडोर होती है और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उद्धार में सरपंच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। श्री शर्मा ने कहा कि यदि उनकी इच्छाशक्ति मजबूत हो, दूरदृष्टि हो और लोगों का साथ हो तो गांवों का कायाकल्प किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पीएम-कुसुम योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है

समीक्षा बैठक

एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के तहत हुए एमओयू को हर हाल में धरातल पर लागू करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित रखा जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर इंटरफेस के माध्यम से निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है, इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि निवेशकों से समय-समय पर प्रगति की जानकारी साझा करें।

भरतपुर व डीग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर व डीग जिले के विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के रोडमैप के जरिए भरतपुर व डीग जिले का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र की भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप आधारभूत विकास परियोजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करते हुए आमजन को लाभान्वित करें।

श्री शर्मा ने कहा कि सड़क, ऊर्जा, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्वायत्त शासन, राजस्व, पर्यटन, वन सहित विभिन्न विभाग आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री ने किया सैडल बांध का निरीक्षण

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अपस्ट्रीम में सैडल डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राणाप्रताप सागर-ब्राह्मणी के बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन एवं उक्त बाढ़ के जल के बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन परियोजना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राणाप्रताप सागर के सैडल डैम के सरप्लस पानी को ब्राह्मणी नदी में डालने के लिए प्रस्तावित कैरिज के मार्ग एवं यहां से पानी बीसलपुर बांध के अपस्ट्रीम तक पहुंचाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से सरप्लस पानी का अधिक से अधिक उपयोग होगा और पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। श्री शर्मा ने यहां स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्षा के जल का संचय कर अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित रावतभाटा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यहां पर परिवहन सुविधा का विस्तार करने सहित अन्य विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।

श्रद्धासुमन

राजभवन में शिवाजी जयंती महोत्सव के दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पर सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर धानक्या में आयोजित प्रार्थना सभा में पं. दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मेल-मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पिछले दिनों देश-दुनिया की कई हस्तियों से मुलाकात हुई।

इनमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली प्रवास के दौरान, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से उदयपुर में, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुलाकात हुई एवं भारत में नार्वे की राजदूत श्रीमती मे-एलिन स्टेनर, योग गुरु स्वामी रामदेव एवं गायक कैलाश खैर मुख्यमंत्री कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट हेतु पहुंचे।

परीक्षा पे चर्चा

विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा की बजाय खुद को बनाएं बेहतर

अभिभावक बच्चों की क्षमता पहचान कर कॅरिअर चुनने में करें मदद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अभिनव पहल से बच्चों के सुखद भविष्य की नींव होगी सुदृढ़ - **मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों के साथ तनाव मुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर के मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम सुना।

देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने उनको परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने और टाइम मैनेजमेंट के उपयोगी सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे परीक्षा का तनाव महसूस न करें तथा अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय खुद को प्रेरित करते हुए बेहतर बनाने का प्रयास करें क्योंकि जो खुद से स्पर्धा करता है, वह जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता। हमें हमारी विफलताओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना निरंतर ज्ञान अर्जित करना है।

जीवन में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान अपने अध्ययन तथा अन्य कार्यों की समय सारणी बनाकर समय का सदुपयोग करते हुए उन्हें सम्पादित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव से उबरने में ध्यान और योग बहुत उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास से तनाव दूर होने के साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने संबंधी टिप्स भी दीं।

अभिभावक बच्चों की अभिरूचि और क्षमताओं को समझें

प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे बच्चों पर अपनी महत्वकांक्षाएं थोपे बिना उनकी अभिरूचि और क्षमताओं को समझें और उनकी पसंद का कॅरियर चुनने में मदद करें। श्री मोदी ने शिक्षकों से भी अपील की कि वे विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने से बचें और संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें।

इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ पोषण, आहार-विहार, मिलेट्स, पर्यावरण संरक्षण तथा "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने बच्चों के साथ पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी हमेशा अपने कर्म, वचन और व्यवहार से देशवासियों को प्रेरित करते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के रूप में उनकी यह अभिनव पहल बच्चों में परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उनके सुखद भविष्य की नींव सुदृढ़ होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया।

श्री जगदीश धाम मन्दिर, कैमरी

छाया एवं आलेख : **अमन हरसाना**

राजस्थान के करौली में कैमरी गांव स्थित जगदीश धाम जन-जन की आस्था का केन्द्र है। कैमरी में माघ सुदी पंचमी विक्रम संवत् 1735 यानी बसंत पंचमी के दिन भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तभी से बसंत पंचमी व आषाढ़ सुदी दौज पर यहां मेला लगता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य व किवंदतियों के अनुसार कैमरी गांव के चन्दनराम (जो आगे चल कर भक्त चन्द्रमादास के नाम से पहचाने गए) ने जगदीश भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प धारण कर जगदीश धाम उड़ीसा के लिए कनक दण्डवत करते हुए प्रस्थान किया। रास्ते में चन्द्रमादास का शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन ईश्वर को याद करने और भक्ति से चन्द्रमादास का शरीर पुनः ऊर्जावान हो गया और वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां उनको भगवान की कृपा से जगन्नाथपुरी जैसी ही तीन मूर्तियां प्राप्त हुईं। चन्द्रमादास के माघ सुदी 4 विक्रम संवत् 1735 को कैमरी गांव पहुंचने पर अगले दिन बसंत पंचमी को मूर्तियों की स्थापना हुई। तभी से यहां हर वर्ष मेला भरता है।

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री जगदीश धाम मन्दिर पहुंचकर दर्शन किए तथा आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होनें "श्री कृष्ण गमन पथ" के अन्तर्गत श्री जगदीश धाम मन्दिर का विकास करवाने की घोषणा की।

राजस्थान सुजस (मासिक)
Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991
20 फरवरी, 2025

वरुण सागर (फॉय सागर)

"गुलामी की पहचान" से मिली मुक्ति

वरुण सागर (फॉय सागर) अजमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण ब्रिटिशराज में फॉय नामक इंजीनियर ने 1891 और 1892 ई. के बीच करवाया था। आनासागर की तरह, फॉय सागर भी बांडी नदी से पोषित (जल प्राप्त करती) है। इसका निर्माण अकाल राहत के दौरान जल प्रबन्धन के लिए कराया गया था। यह एक कृत्रिम वाटर बॉडी है जो पड़ोस में अवस्थित अरावली पर्वत का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। हाल ही में राज्य सरकार ने अजमेर में तीन स्थानों के गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नाम बदले है जिसमें फॉय सागर झील का नाम "वरुण सागर" करने के साथ ही होटल खादिम का नाम होटल "अजयमेरू" और किंग एडवर्ड मेमोरियल (रेस्ट हाउस) का नाम बदलकर "महर्षि दयानन्द विश्रान्तिगृह" कर दिया है।

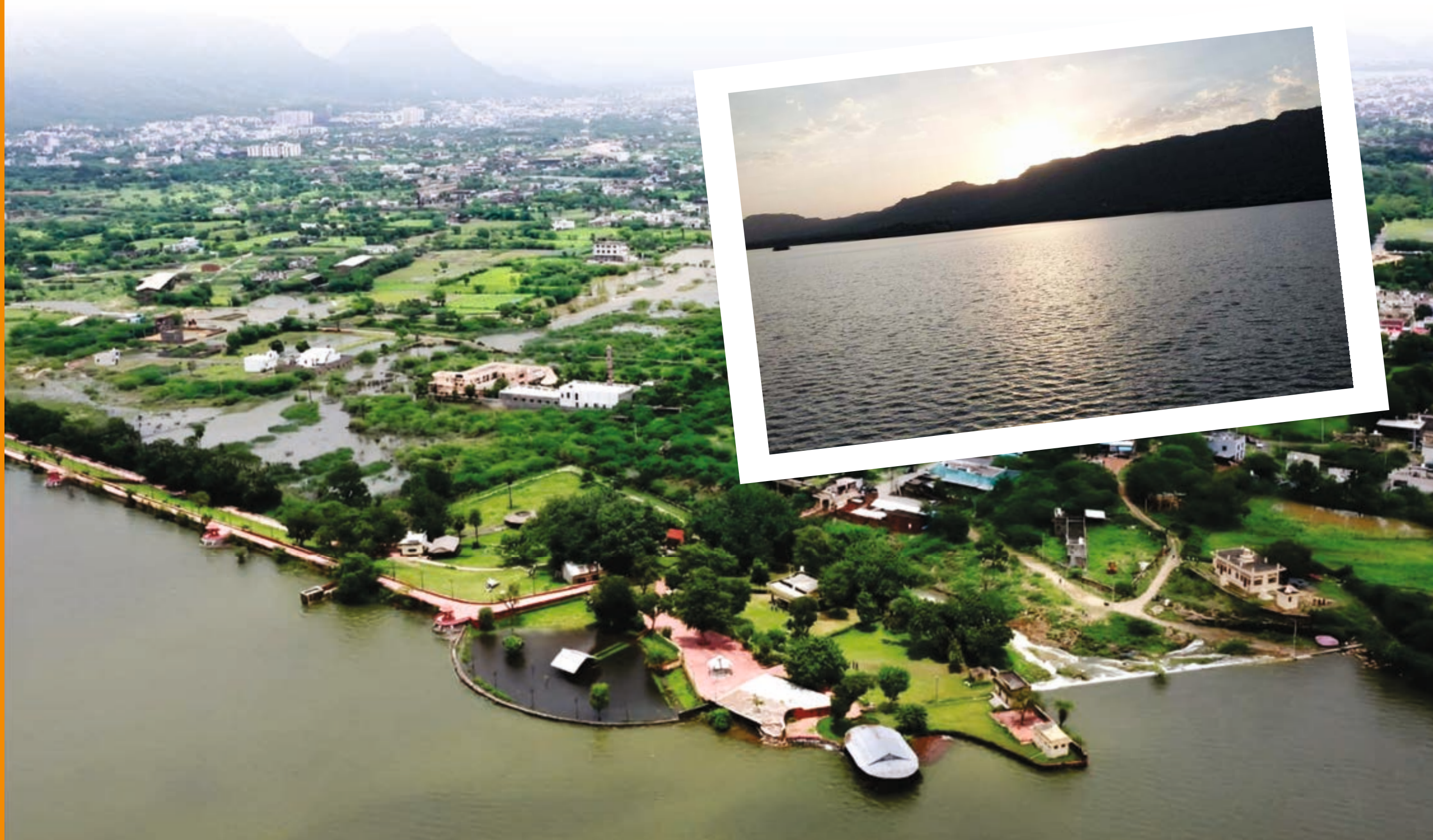

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - डॉ. रजनीश शर्मा, मैसर्स .... जयपुर से मुद्रित(25,000 प्रतियां), 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 76,000